



# जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

## 370 हटाने से कांग्रेस के पेट में दर्द : मोदी

गोहाना/ हिसार, 18 अक्टूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के रुख के लिए उसकी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान विपक्षी दल के बयानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। उन्होंने पूछा कि आखिर पड़ोसी देश के साथ उसकी (कांग्रेस की) किस तरह की 'केमिस्ट्री' है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से कांग्रेस के पेट में दर्द है।



प्रधानमंत्री ने कहा, अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए वे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो पाकिस्तान को परसंद आते हैं।

को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जैसे दल न तो लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, न ही बहादुर जवानों की शहादत के प्रति सम्मान करते हैं।

यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने उपस्थित लोगों से पूछा, 'क्या मुझे राष्ट्रहित में फैसले लेने चाहिए या नहीं, क्या राष्ट्रहित राजनीति से ऊपर होने चाहिए या नहीं? लेकिन कांग्रेस हरियाणा के लोगों की, सोनीपत के लोगों की यह भावना समझने में नाकाम है।' कांग्रेस पर

तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पांच



विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

## शाह का निर्देश, दफ्तरों में पटेल की तस्वीर लगाएं सुरक्षा बल

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों को अपने कार्यालयों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी। यह निर्देश 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती से पहले दिया गया। गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को 'भारत की सुरक्षा और एकता को हम अक्षुण्ण रखेंगे' संदेश के साथ पटेल की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया है।



यह निर्देश पटेल जयंती से पहले दिया गया।

## अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं एसए बोबडे

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने शुक्रवार को केंद्र को एक पत्र भेजकर वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति गोगोई ने विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति बोबडे को अगला प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति गोगोई ने तीन अक्टूबर 2018 को देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर

शपथ ग्रहण की थी। वे 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश ने परंपरा के मुताबिक अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बाद अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक होगा।

नागपुर में जन्मे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे की पढ़ाई भी वहीं हुई। उन्होंने 1978 में बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत शुरू की और वर्ष 2000 में वहीं हाई कोर्ट

जज बने। वे अक्टूबर 2012 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 12



प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्र को पत्र भेजकर न्यायमूर्ति बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की।

## आतंक के लिए वित्तपोषण : पर्याप्त कार्रवाई में इस्लामाबाद रहा नाकाम

# पाक को चार महीने की मोहलत

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

आतंकवाद को मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक की मोहलत दी है और उसे अपनी 'ग्रे सूची' में बरकरार रखा है। धन शोधन (मनी लांड्रिंग) और आतंकवाद को धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में इस्लामाबाद के नाकाम रहने को लेकर यह कदम उठाया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल



(एफएटीएफ) की पेरिस में पांच दिनों तक चली पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को एक और

काली सूची से बचाया चीन, मलेशिया और तुर्की ने

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

चीन, मलेशिया और तुर्की के समर्थन के कारण पाकिस्तान काली सूची में जाने से बच गया। अधिकारियों के

## हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी की हत्या

लखनऊ, 18 अक्टूबर (जनसत्ता)।

लखनऊ में शुक्रवार को घनी आबादी वाले नाका हिंडोला इलाके में शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। तिवारी पूर्व में हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। कमलेश की पत्नी किरण की शिकायत पर इस मामले में मुफ्ती नईम काजमी और अनवारुल हक तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किरण का आरोप है कि काजमी और हक ने 2016 में कमलेश का सिर कलम करने पर क्रम से 51 लाख और डेढ़ करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। इन्हीं लोगों ने साजिश



हत्याओं ने गला रेतने के बाद मारी गोली, आइएस के निशाने पर भी थे कमलेश

## दमघोंटू औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 पर, पराली जलाने से समस्या बढ़ी

# दिल्ली की आबोहवा हुई और खराब

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में शुक्रवार की सुबह से हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की हो गई। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (आइक्यू) 306 तक पहुंच गई। आगे इसमें और गिरावट की आशंका है। हवा में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने की वजह से दिन भर धुंध की चादर छाई रही जिससे बादल जैसा नजारा रहा। यहां तक कि दृश्यता में भी गिरावट देखने को मिली।



मुताबिक राजधानी में शुक्रवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 रहा। यह गुरुवार को 270 था। शनिवार व रविवार सहित अगले

हफ्ते में इसके और खराब होने की आशंका है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली टेक्नोलॉजिकल

बाकी पेज 8 पर

## आइएनएक्स मीडिया मामला

# चिदंबरम व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को एक आरोपपत्र दायर किया। यह आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया। इसमें पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमण, नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, प्रबोध सक्सेना, रविंद्र प्रसाद, आइएनएक्स मीडिया, एएससीएल और चैस मैनेजमेंट सर्विसेज को भी आरोपी बनाया गया है। अंतिम रिपोर्ट में आरोपी से सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी का भी नाम है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ इस मामले पर 21 अक्टूबर को विचार करेंगे।



आरोपी से सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी आरोपपत्र में शामिल अदालत आरोपपत्र पर 21 अक्टूबर को लेगी संज्ञान

## 'जेल में 43 दिन में पांच किलो वजन कम हुआ'

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जेल में पिछले 43 दिन में उनका पांच किलो वजन कम हो चुका है और वह दो बार बीमार पड़ चुके हैं। चिदंबरम ने मामले में शीर्ष अदालत से जमानत की मांग की और कहा कि दो बार बीमार पड़ने के बाद उन्हें एंटीबायोटिक दिए गए।

जेल में दो बार बीमार रहने की बात भी बताई सुप्रीम कोर्ट को

बाकी पेज 8 पर

अदालत से कहा कि छह सितंबर से एंजंसी ने 12 गवाहों से पूछताछ की और अंतिम पूछताछ भी अक्टूबर को हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान ईडी ने कुछ अतिरिक्त सबूत भी जमा किए। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके चिदंबरम को 21 अगस्त को जोर बाग स्थित उनके निवास से सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज कर आइएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया था। उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि आइएनएक्स मीडिया समूह में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) की अनुमति दिलाने के लिए चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और अपने बेटे कार्ति के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा की घूस ली थी। पूछताछ में इंद्राणी बता चुकी है कि एफआइपीबी की मंजूरी के सिलसिले में वे कार्ति चिदंबरम से मिली थीं। इस मामले में कार्ति चिदंबरम पर प्रमुख आरोप ये है कि पिता के वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने इसका फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।

**TORQUE**

अब दाग-धब्बों की चिंता क्यों!

दाग-धब्बों रहित दमकती त्वचा को पाने के लिए **NO SCARS** का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और पाईये सितारों सा चमकता चेहरा।

Also Available

Get dazzling Glamour with...

अधिक समय तक चलने वाला प्रीमियम क्वालिटी साबुन

किसी महिला को ओर कोई बात उतना खूबसूरत नहीं बनाती, जितना कि खूबसूरत होने का उसका विश्वास। यही विश्वास उसकी आंतरिक सौंदर्यता को बाहर निखारता है। **No Scars** सौंदर्य साबुन आपकी त्वचा को मुलायम व आकर्षक बनाने में मदद करता है। **No Scars** के तत्व ही इसे एक बेहतरीन नमी प्रदान करने वाला और हर प्रकार की त्वचा को पोषण देने वाला बनाता है।

PREMIUM QUALITY SOAP

100% Pure Vegetarian Soap

**NO SCARS**

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: +91 97792 14455 / care@torquepharma.com

**TOREX**

चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और अपने बेटे कार्ति के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा की घूस ली थी। पूछताछ में इंद्राणी बता चुकी है कि एफआइपीबी की मंजूरी के सिलसिले में वे कार्ति चिदंबरम से मिली थीं। इस मामले में कार्ति चिदंबरम पर प्रमुख आरोप ये है कि पिता के वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने इसका फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।









## थकाऊ और पकाऊ



**लाल कप्तान**  
 रेटिंग- ★★  
 निर्देशक- नवदीप सिंह

**कलाकार-** सैफ अली खान, दीपक डोब्रियाल, मानव विज, जोया हसन

क्या सैफ अली खान का करियर अब ढलान पर है? लगता तो यही है क्योंकि 'सेक्रेड गेम्स' के दूसरे सीजन में वे जम नहीं पाए और पिछले बरसों में उनकी फिल्में भी पीटी ही हैं। उनकी नई फिल्म 'लाल कप्तान' भी पकाऊ और थकाऊ है। इसमें सैफ गोसाई नाम के (हालांकि गोसाई कोई नाम नहीं है, हर साधु को गोसाई कह सकते हैं) नागा साधु बने हैं, जो प्रतिशोध लेने निकला है। रहमत खान (मानव विज) नाम के शख्स से। फिल्म की कहानी

अठारहवीं सदी के भारत पर केंद्रित है। बक्सर के युद्ध के समय की। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक पीरियड फिल्म है। जिस क्षेत्र की कहानी है, वह है भारत का बुंदेलखंड। क्या गोसाई बदला ले पाएगा? लेकिन बदला किस बात का? गोसाई रहमत खान को खोजने निकला है। ये खोज आसान नहीं है। कई तरह की पेचीदगियां हैं। क्या गोसाई अपने मकसद में कामयाब होगा।

रहमत खान और गोसाई-दोनों खूंखार हैं। इसलिए कई जगहों पर अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है। यह भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म में सैफ या दूसरे कलाकारों से ज्यादा असफलता इसके निर्देशक नवदीप सिंह की है जो कहानी को ठीक से समेट नहीं पाते। सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में आइटम सांग किया है। वह भी बेमतलब का है।

## सुस्त और बोरियत भरी

**यारम**  
 रेटिंग- ★  
 निर्देशक- ओवेश खान

**कलाकार-** प्रतीक बब्बर, इशिता राज शर्मा, सिद्धांत कपूर, अनीता राज, दिलीप ताहिल

फिल्म का मूल आइडिया तो यह है कि दर्शकों को बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के बीच प्रचलित रहे तीन तलाक को जो कानून खत्म किया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका दूसरा मकसद यह है कि प्रतीक बब्बर को बतौर हीरो पेश किया जाए। प्रतीक ने इसमें रोहित नाम के एक शख्स का किरदार निभाया है। रोहित का दोस्त है साहिल (सिद्धांत कपूर)। साहिल की बीवी है जोया (इशिता राज

शर्मा)। साहिल और जोया में अनबन हो जाती है और फिर तलाक तलाक तलाक। फिर साहिल का मन बदलता है और जोया से फिर शादी करना चाहता है। इसके लिए इस्लाम के मुताबिक हलाला जरूरी है यानी जोया को पहले किसी और से शादी करनी होगी। क्या ऐसे में उसका दोस्त रोहित काम आएगा? पर रोहित को अपना मजहब बदलना होगा। लेकिन क्या होगा अगर रोहित और जोया में प्यार हो जाए तो?

ऐसे ही उलझनों से गुजरने वाली यह फिल्म बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ती है और दर्शकों को लगातार बोर करती हुई जब अंत तक पहुंचती है तब पता चलता है कि निर्देशक यह बताना चाहता है कि तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं गलत हैं। पर फिल्म यह नहीं बताती है कि अगर पत्नी और पति में रिश्ते खराब हो जाएं तो क्या निदान हो।

## नीति आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली का अव्वल दर्जा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

नीति आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली नंबर वन बनी है। इस रिपोर्ट पर आम आम आदमी पार्टी के नेता अर्जुन कुमार ने कहा कि दिल्ली के बेहतर गवर्नेंस मॉडल की बदौलत यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इस मॉडल को खुद केंद्र सरकार ने एक सबसे बेहतर मॉडल बताया है। देशभर के सभी राज्यों में दिल्ली सबसे आगे रही है। यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी

और आम जनता के स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही बिजली बिल हाफ व पानी बिल माफ की योजना को लागू किया था।

इस सफल प्रयास के बाद से ही जनता को जोड़ने के लिए पार्टी ने एक के बाद एक योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन योजनाओं से भाजपा भी परेशान है। भाजपा नेता विजय गोयल ने खुद जनता को ही जा रही इन मुफ्त योजनाओं पर सवाल खड़ा किया है।

## जामिया में उर्दू भाषा के एक साल के पाठ्यक्रम की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से उर्दू भाषा में एक साल के पाठ्यक्रम में दाखिले की पेशकश की है। इस

पाठ्यक्रम का मकसद उर्दू सीखने की खाहिश रखने वालों के लिए अवसर प्रदान करना है। दूरस्थ माध्यम वाले इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पूरे वर्ष किसी भी समय लिया जा सकता है। यह कोर्स छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार उर्दू सीखने की सुविधा प्रदान

करती है। भारत में इस कोर्स के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपए है जबकि दक्षिण (साक) देशों के लोगों के लिए 20 अमेरिकी डॉलर और अन्य देशों के लिए 50 अमेरिकी डॉलर है। यह कोर्स करने वालों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।

**कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल**  
 (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)  
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
 कृषि अनुसंधान भवन-1, पुरा, नई दिल्ली 110 012

मिखिल सं. 1(8)/2019-परीक्षा.11 दिनांक 14 अक्टूबर, 2019

**सूचना**  
**भा.कृ.अनु.प. - राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) - 2019**

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ए.एस.आर.बी.), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.) / कृषि विश्वविद्यालय (ए.यू.) में व्याख्याता / सहायक प्रोफेसर के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए सम्पूर्ण भारत में 34 केंद्रों पर ऑनलाइन माध्यम से (कंप्यूटर-आधारित परीक्षा) योग्यता परीक्षा, भा.कृ.अनु.प. - राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) -2019 परीक्षा आयोजित करेगा।

अधिक विवरण वेबसाइट [www.asrb.org.in](http://www.asrb.org.in) और [www.icar.org.in](http://www.icar.org.in) पर प्राप्त किया जा सकता है।

हस्ता./-  
 (वेद प्रकाश)  
 परीक्षा नियंत्रक  
 davp 01307/11/0005/1920

**फार्म ए**  
**सार्वजनिक उद्घोषणा**  
 भारतीय विद्यालय और स्कूल अधिनियम 2017 (संशोधित संस्करण अधिनियम 2017 के विधेयक 14 के अंतर्गत)  
**स्वयं सेवक एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड के हिताधारकों के ध्यानार्थ**

1. कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	स्वयं सेवक एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि	11/01/2010
3. प्राधिकृत जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय U52100DL2019PTC354826
4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट व्यक्ति की संख्या	501, प्लॉट नं. 17, सचदेवा कॉर्पोरेशन टॉवर कम्युनिटी सेक्टर, ककरकल्ला, दिल्ली ईस्ट दिल्ली, 110092
6. कॉर्पोरेट व्यक्ति के संबंध में दिनांक प्राप्त तिथि	18 अक्टूबर, 2019
7. परिवर्तन का नाम, पता, ई-मेल पता और टेलीफोन नंबर ध्वंसीकरण संख्या	करुणा शर्मा जी-13, फ्लैट फ्लोर, सार्वज 2-2, सेक्टर-50 मुजगांव हरियाणा -122018 ईमेल आई डी : sharma.karuna@gmail.com सफाई विभाग : 9871145777 पंजीकरण संख्या : BB/MPA/002/PA-N003402017-18/10944
8. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	17 अक्टूबर, 2019

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्वयं सेवक एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड ने 18 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। स्वयं सेवक एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड के सभी हिताधारकों को उपरोक्त मद सं. 7 में वर्णित कार्यालय पते पर अपने दावों के प्रमाण परिसमापक के पास 17 नवंबर, 2019 तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विधेयक लेनदार अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ताक्षर /-  
 करुणा शर्मा  
 इन्स्ट्रान्सेवी प्रोफेशनल

पंजीकरण संख्या : BB/MPA/002/PA-N003402017-18/10944  
 sharma.karuna@gmail.com, मोबाइल-9871145777  
 जी-13, फ्लैट फ्लोर, सार्वज 2-2, सेक्टर-50 मुजगांव हरियाणा -122018

दिनांक : 18 अक्टूबर 2019  
 स्थान : नई दिल्ली

**दिल्ली पुलिस**  
 शांति सेवा न्याय

# प्रहरी

DP/19/163/19

**'प्रहरी' (दिल्ली पुलिस की एक पहल) में हम निवासियों और मार्केट वेलफेयर एसोसिएसन्स के साथ मिल कर चौकीदारों और सिव्युरिटी गार्ड्स जो हमारे साथ काम करते हैं को और अधिक सजग-संवेदनशील बना रहे हैं ताकि हम सब आपको बेहतर सेवा दे सकें।**

**बेहतर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सिव्युरिटी गार्ड्स की नियुक्ति करें और उन्हें प्रहरी का हिस्सा बनाएं**

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: [cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in](mailto:cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in) | लिखें: पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर कॉल करें

पुलिस को सूचना देने के लिए 1090 पर कॉल करें

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...the name you can BANK upon!

सकिल कार्यालय : बुलन्दशहर  
 पता : यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001  
 मोबाइल : 9897912444, फोन : 05732-281724, ई-मेल : [cobrsamd@pnb.co.in](mailto:cobrsamd@pnb.co.in)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत जनसामान्य को ई-नीलामी विक्रय की सूचना, अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पंजाब प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आसतियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आसतियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रॉ), गिरवीकर्ता (ऑ) तथा जमानती (यॉ) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा किया है, का विक्रय निम्नलिखित नामधारी कर्जदार (रॉ), गिरवीकर्ता (ऑ) तथा जमानती (यॉ) से पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत लेनदार की ओर नीचे वर्णित बकायों की राशि की वसूली के लिए "जहाँ है वहाँ है", "जो कुछ है यही है" तथा "जो भी है वहाँ है" के आधार पर 28.11.2019 को किया जायेगा। ज्ञात अग्रधारों, यदि कोई हो, सहित अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया (1) <https://www.pnbindia.in>, (2) <https://www.pnbindia.biz>, (3) <https://eprocure.gov.in/epublish/app> में प्रावधानित लिंक देखें।

**ई-नीलामी का कार्यक्रम**

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ज.ध.रा. जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
25.11.2019 (सोमवार) 12:00 बजे प्रातः से 16:00 बजे अपराह्न तक	26.11.2019 (मंगलवार) 16:00 बजे अपराह्न तक	28.11.2019 (बृहस्पतिवार) 12:00 बजे दोपहर से 14:00 बजे अपराह्न तक

**प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची**

क्रम सं.	कर्जदार का नाम तथा शाखा	स्वामी (यॉ)/सम्पत्ति (यॉ) के निरवलीकर्ताओं का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	निरवलीकृत सम्पत्ति (यॉ) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ज.ध.रा.	सर्काराणी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि	सर्काराणी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि
1.	मैसर्स भारत बायोकोलोन शाखा : सिविल लाइन बुलन्दशहर	श्री सुनील सिंह	रु. 94,41,141.92/- + 01.01.2019 से ब्याज	ग्राम अशरफपुर, खानपुर रोड, खसरा नं. 13, 27, 29एम, 33, 34 तथा 38, तहसील-सियाना, बुलन्दशहर, क्षेत्रफल 1.922 हेक्टे.	रु. 1,65,00,000/- (रु. एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)	रु. 16,50,000 (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र)	02.02.2019	13.05.2019 (संकेतिक कब्जा)

**ई-नीलामी विक्रय के नियम एवं शर्तें :**

i. विक्रय प्रक्रिया प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा पुनः निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सम्पन्न होगी :  
 ii. सम्पत्तियों का विक्रय "जहाँ है वहाँ है", "जो कुछ है यही है" तथा "जो भी है वहाँ है" के आधार पर किया जा रहा है।  
 iii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आसतियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना पर लिखे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्णता अथवा त्रुटिपूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।  
 iv. प्रतिभूत आसत का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।  
 v. नीलामी विक्रय "ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से" पोर्टल <https://etender.pnbnet.in> ; [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) ; [www.eprocure.gov.in/epublish/app](http://www.eprocure.gov.in/epublish/app) के माध्यम से किया जायेगा।  
 vi. संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय कार्यक्रमों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल <https://etender.pnbnet.in> ; [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) ; [www.eprocure.gov.in/epublish/app को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है तथा/अथवा सम्पर्क करें : श्री कमल किशोर ठाकुर, मुख्य प्रबन्धक, अधिकृत प्राधिकारी \(मोबाइल नं. 8171113715\)  
 vii. इच्छुक पर्यवेक्षक ज.ध.रा. उपायुक्त तालिका में उल्लिखित तिथि तक डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक" के पक्ष में अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते-पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता सं. 4568002100002378, \(आईएफएससी कोड डबल0456800\) में जमा करनी होगी। ड्राफ्ट किसी सहकारी बैंक का नहीं होना चाहिए।  
 viii. इसके पर्यवेक्षक ज.ध.रा. जमा करने के उपरान्त सविदाकार अग्रलिखित दस्तावेज जमा करेंगे-1. ज.ध.रा. जमा होने का प्रमाण \(जब एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से हो\) अथवा मूल रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट \(जहाँ भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित हो\), 2. पहचान प्रमाण-पत्र अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गयी प्रतियाँ, 3. आवसीय पते का प्रमाण, 4. \(अ\) संविदाकार का नाम, \(ब\) मोबाइल नं./सम्पर्क नं., \(ग\) पता, \(घ\) ई-मेल का पता, \(ङ\) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलौदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलौदाताओं को ई-बोली के लिये उपयुक्त नॉडेट कॉपी भी जमा करना होगा। बोलौदाता को ई-मेल \[cobrsamd@pnb.co.in\]\(mailto:cobrsamd@pnb.co.in\) के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ ही "खाता क्रम सं. आईपी में बोली" के रूप में सौभाग्यवश मुहूर्त्त लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों \(मूल डिमांड ड्राफ्ट\) के स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।  
 ix. इच्छुक बोलौदाता को मुख्य प्रबंधक, श्री राजवीर सिंह \(मो.नं. 8800305533, सकलित कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001\) से अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पारवर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पारवर्ड बोलौदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलौदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।  
 x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलौतियों को स्वीकार या निराल करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी की फिलियाम/दृष्ट्यापित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।  
 xi. बोलौदाता रु. 20,000/- \(रु. बीस हजार मात्र\) के गणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।  
 xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलौदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। 'ऑन लाइन नीलामी' की सम्पत्ति के बाद उच्चतम बोलौदाता को सफल बोलौदाता घोषित किया जायेगा तथा वह विक्री प्रतिभूत क्रेडिट द्वारा पुरिष्ठ के अधीन होगी।  
 xiii. सफल बोलौदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. 4, में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोलौती/विक्री राशि \(जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है\) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोलौती राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जन्म कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से विक्री की जायेगी।  
 xiv. सफल बोलौदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 25% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जन्म कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की विक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जायेगी।  
 xv. यदि विक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उसके पूर्व किसी भी समय अग्रधारक या गारन्टर/रॉ के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्च अथवा जमा की जाने वाली राशि/स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की विक्री रद्द कर दी जायेगी।  
 xvi. पंजीकरण चार्जज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांख्यिक बकायों/एटैन्टेड चार्जज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।  
 xvii. विक्री प्रमाण पत्र विक्री का रसीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।  
 xviii. बिन बोलौदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री राजवीर सिंह मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी \(मो. नं. 8800305533, सकलित कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम से सम्पर्क कर सकते हैं।  
 xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार नहीं है। ई-नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिखित, अधिभार अथवा सरदार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकायों के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलौदाता को सलाह दी जाती है कि सांख्यिक देवताओं, सम्पत्ति कर के बकायों, बिजली के बकायों आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।  
 xx. बोलौदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैंक-अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट कनेक्शन, पावर बैंक-अप आदि सुनिश्चित करने वाले तकनीकी कारणों/आकरिसिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।  
 xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।](http://www.eprocure.gov.in/epublish/app)

"बैंक ने सर्फाएणी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, बुलन्दशहर के पास भौतिक कब्जे के लिये आवेदन दाखिल कर दिया है।

लिखित: 18.10.2019  
 स्थान: बुलन्दशहर

अधिकृत प्राधिकारी,  
 पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर



## दिल्ली विस अध्यक्ष सहित पांच लोगों को छह महीने की सजा

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

दिल्ली की निचली अदालत ने घर में जबरन घुसने के जुर्म में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने की सजा सुनाई है। गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत पांच लोगों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है। सुमित को मारपीट करने का भी दोषी पाया है। उन सभी पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्र के अलावा जिन तीन लोगों को सजा हुई उनमें अध्यक्ष के सहयोगी हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि कानूनी प्रावधानों के तहत सभी दोषियों को हाथोंहाथ जमानत भी मिल गई ताकि वे उपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। उन्हें एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर अदालत ने जमानत दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने गोयल और चार अन्य आरोपियों को यह कहते हुए दोषी करार दिया। जज ने कहा कि उनके खिलाफ यह मामला संदेह के परे है। लिहाजा इन्हें सजा मिलनी चाहिए। भाजपा नेता मनीष घई ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले अदालत ने गोयल को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया। रामनिवास गोयल के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया। मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ विवेक विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी उस वक्त गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे। यह मामला



करीब पांच साल पहले घर में जबरन प्रवेश करने और मारपीट करने का मामला

छह फरवरी, 2015 का है। ये सभी लोग पीड़ित के घर में घुस गए थे और उनमें से कुछ ने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि रामनिवास गोयल ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले वोट के लिए बांटी जानी थी। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ पीड़ित के घर में दाखिल हुए थे। लेकिन अदालत ने गोयल और अन्य की दलीलों की जगह शिकायती पक्ष की दलीलों से सहमति जताई और उन्हें दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माना किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके घर में काम चल रहा था और कुछ मजदूर वहां रह रहे थे। छह फरवरी, 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे गोयल व उनके साथियों ने घर में जबरन प्रवेश किया। मजदूरों ने उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। आरोपपत्र के मुताबिक आरोपियों ने वहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मजदूरों ने जब विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई।

### भाजपा ने घेरा

#### ‘दागदारों को मुख्यमंत्री का संरक्षण’

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दागदार नेताओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का सही चेहरा सामने आ गया है। यह मामला चार साल पुराना है और आज अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि रामनिवास गोयल ने अपने बेटे सुमित गोयल के साथ भाजपा कार्यकर्ता मनीष घई के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अदालत के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है।



#### इस्तीफा दें गोयल : गुप्ता

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी प्रकार नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में विधायक का लिफ्ट होना यह मुख्यमंत्री की नरमी का प्रतीक है। उन्हें अपने पद की गरिमा के लिए पद से इस्तीफा देना चाहिए।



## पूर्व क्रिकेटर प्रभाकर और उनकी पत्नी पर मकान कब्जाने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, उनकी पत्नी और बेटे समेत दो अन्य सहयोगी पर एक बुजुर्ग महिला ने उनके फ्लैट पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मालवीय नगर थाने में शिकायत दी है। शिकायत करने वाली बुजुर्ग महिला विदेश में रहती है। उनका आरोप है कि भारत में नहीं होने का फायदा उठाते हुए उनके फ्लैट पर कब्जा किया गया है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक आरोप लगाने वाली संध्या शर्मा इन दिनों लंदन में रहती हैं। उन्होंने बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर समेत पांच लोगों के खिलाफ उनके फ्लैट पर अवैध कब्जा करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनका सर्वप्रिया विहार इलाके में एक फ्लैट है। उसी अपार्टमेंट में मनोज प्रभाकर भी पहली मंजिल पर रहते हैं। महिला का दावा है कि उनकी गैरमौजूदगी में उनके फ्लैट के फर्नीचर कागजात बनवाकर उन्होंने फ्लैट पर कब्जा कर लिया। उनके फ्लैट का ताला भी तोड़ दिया और उसमें अपने एक जानकार को रहने के लिए जगह भी दे दी। महिला ने विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई और फ्लैट के बदले डेढ़ करोड़ की मांग की गई।

## टूटी और खराब सड़कों के लिए एजंसियों पर लगेगा जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अब सख्ती बढ़ाएगी। धूल कण व प्रदूषण की एक बड़ी वजह टूटी हुई सड़कें भी हैं। इन सड़कें मार्गों की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली के सभी एसडीएम को आदेश दिए हैं कि वे ऐसे मार्गों की जांच करें और खराब पड़े मार्गों के लिए संबंधित एजेंसियों पर जुर्माना लगाएं।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने मार्गों का सर्वे किया था। इस सर्वे के बाद शुरुआत तक सभी मार्गों को ठीक करने के आदेश दिए थे। इस प्रक्रिया के बाद ही एसडीएम को ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों के धूल भरे मार्गों की पहचान करेंगे और इस मामले में उन एजेंसियों पर जुर्माना लगाएंगे। दिल्ली में 1260 किलोमीटर लंबे प्रमुख मार्ग दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास हैं। प्रदूषण की स्थिति का अध्ययन करने के लिए शुरुआत को मंत्री कैलाश गहलोत ने द्वारका के केंद्र का भी मुआयना किया। प्रदूषण के आकलन के लिए सरकार ने यह केंद्र तैयार किया है।

वहीं प्रदूषण के मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण जांच एजेंसियों को घेरा है। शुरुआत को पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश की जांच एजेंसियां हरियाणा व पंजाब को बचाने में लगी हैं। इसलिए बार-बार ऐसे आकलन पेश किए जा रहे हैं जिसमें यह बताने का कोशिश हो रही है कि पराली की वजह से प्रदूषण नहीं है। उनका इशारा शुरुआत को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीसी) द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की तरफ था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। इसके बाद

### एनजीटी ने दिया द्वारका में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई का आदेश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को द्वारका के एक आवासीय क्षेत्र के आस पास ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ये आदेश द्वारका के सेक्टर-3 में ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) से दो महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पीठ ने कहा कि डीपीसीसी मामलों की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की एक याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए कहा कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की एक याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए कहा कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। याचिका के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए डीजल जेनरेटर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने में लगे पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश से राहत मांगी गई थी।

### नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली वितरण कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। याचिका के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए डीजल जेनरेटर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने में लगे पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश से राहत मांगी गई थी।

से ही एजेंसियों में होड़ लगी हुई है कि दिल्ली के लोग प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

## विधानसभा अध्यक्ष के सचिव से पश्चिम विहार में झपटमारी

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

पश्चिम विहार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के सचिव का मोबाइल झपट लिया। घटना के समय पीड़ित अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर के पास स्थित बाजार में जा रहे थे। पुलिस को शाम करीब 7 बजकर 15 मिनट पर सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस ने सचिव अजय रावल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर तलाश में जुटी है। बीते दिनों स्कूटी सवार बदमाशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी का बैग झपट लिया था, जिसमें नकदी, मोबाइल फोन समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे।

अजय रावल अपने परिवार के साथ पश्चिम विहार में रहते हैं। गुरुवार को अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक विहार में केंद्रीय विद्यालय के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश आए और उनका मोबाइल झपट लिया।

### कनाट प्लेस में वायुसेना के अधिकारी का बैग झपटा

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

राजधानी के कनाट प्लेस (सीपी) में एक वायुसेना के अधिकारी से बैग झपटमारी का मामला सामने आया है। पीड़ित अधिकारी जार्ज थॉमस (50) ने बैग को साइकिल के हैंडल पर टंगा हुआ था। वारदात के समय वह साइकिल चला रहे थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब छह बजे वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित जार्ज थॉमस सेना भवन में ठहरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को अपने घर की बजाए दफ्तर का ही पता बताया है। वह गुरुवार सुबह साइकिल चलाते हुए कनाट प्लेस के आउटर सर्कल से बाबा खड़क सिंह मार्ग से होते हुए बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने साइकिल के आगे हैंडल पर एक छोटे सा बैग लटकाया हुआ था, जिसमें उनका मोबाइल फोन और पर्स था।

## राहुल को है प्रधानमंत्री से ‘एलर्जी’ : राजनाथ

फरीदाबाद, 18 अक्टूबर (जनसत्ता)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘एलर्जी’ है। देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए राफेल खरीदने की चर्चा 10-12 सालों से चल रही थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाकर फैसला कर दिया। अब वह प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। सिंह शुरुआत को पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव खंड्यसा में भाजपा उम्मीदवार सोहनपाल छोकर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे।

रक्षामंत्री ने कहा कि राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर हैं, वह प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष किसी नेता के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश की गरिमा व प्रतिष्ठा किसी भी

### नागर को पायलट समझकर वोट दें : सचिन

फरीदाबाद। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ का पिटारा लेकर घूमने वाले भाजपाइयों के दिन अब लद चुके हैं। सामने खुल चुकी है। भाजपा के 75 पार का नारा भी लोगों ने नकार दिया है। इसलिए अब वक्त आ गया है इन जुमलेबाजों को प्रदेश से चलता करने के लिए कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि तिगांव को कांग्रेस के प्रत्याशी ललित नागर को सचिन पायलट समझकर विधानसभा में भेजने का काम करें। उन्हें हरियाणा में बनने वाली

कांग्रेस सरकार में बड़े पद का मंत्री बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सचिन पायलट शुरुआत को तिगांव अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए कहा कि पांच साल पूर्व 2014 के विधानसभा चुनावों में मैं भी इसी तिगांव की अनाज मंडी में आम लोगों के बीच आया था और आपने मुझे मान देते हुए ललित नागर के रूप में विजयी ताज पहनाया था। इसलिए आज फिर मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में अन्याय रूपी भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। (जनसत्ता)

मर्यादा पुरुषोत्तम की परंपरा को निभाया। रक्षामंत्री ने कहा कि राफेल खरीद में राहुल गांधी चोरी का आरोप लगाते हैं, यह एक गाली है, जो गलत है। उन्होंने कहा

सूरत में नहीं गिरनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर उन्हें राजनीति नहीं करनी आती तो वह रामायण ही पढ़ लें, कैसे भगवान राम ने

### लेडी श्रीराम कॉलेज के पास पुलिस से मुठभेड़

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लेडी श्रीराम कॉलेज के पास से शुरुआत सुबह मुठभेड़ के बाद एक लाख रुपए के इनामी बदमाश इकबाल को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी। इसी बीच तीन पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। इकबाल के खिलाफ विभिन्न थानों में डकैती, लूटपाट, चोरी, पुलिस पर हमला करने समेत कई मामले दर्ज हैं। (ज.सं.)

### सूटकेस में बंद मिला महिला का शव

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

बवाना थाना क्षेत्र में शुरुआत सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लोगों एक लावारिस बैग को देखा। बैग से बंदबू आ रही थी। आनन-फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बैग खोल कर देखा तो अंदर एक महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में था। पुलिस ने बताया कि महिला के पास से

कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस मानकर चल रही है कि महिला का शव तीन-चार दिन पुराना हो चुका है।

फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यहां पर बैग कौन फेंक कर गया होगा। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है।

<b>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया</b> <b>Central Bank of India</b> <small>1911 में आपके लिए "केबलिंग" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911</small>		<b>कब्जा सूचना</b> <small>(अवकाश सम्पत्तियों के लिए)</small> <small>[[विशिष्ट-IV]]केब्रे नियम 8(11)</small>			
<b>शाखा कार्यालय: एमएमएच कॉलेज, गाजियाबाद, ७०५०</b>					
<b>एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक छाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज को लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-</b>					
<b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b>					
क्र.सं.	ऋणधारक/गारंटर्स के नाम	गिरवी रखी गई/वाजद सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	33(2) मुक्त बंध अनुसार बकाया राशि
1.	<b>कर्जदार :</b> <b>श्री लाजवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह एवं श्रीमती अल्पना सिंह पत्नी लाजवन्त सिंह</b>	<b>प्राथमिक सुरक्षा:</b> श्री लाजवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम में ईएम आवासीय सम्पत्ति दूसरा तल परिया 50 वर्ग मीटर, गाँव दरगल के खसरा नं.1025 में सम्बन्धित प्लॉट नं.35ए पर निर्मित, अब गुलवार-2, न्यू फ्रेंड्स कालोनी गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है। सम्पत्ति जो घिरा है: पूर्व: रास्ता 24 फीट पश्चिम: प्लॉट नं.58 उत्तर: प्लॉट नं.35 दक्षिण: प्लॉट नं.36	03.06.2019	14.10.2019	₹. 14,17,425/- और उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार/व्यय।
2.	<b>कर्जदार :</b> <b>श्री कृष्ण कुमार पुत्र धर्म वत्त एवं श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी कृष्ण कुमार</b>	<b>प्राथमिक सुरक्षा:</b> ईएम निर्मित वृंदावन गार्डन में स्थित आवासीय सम्पत्ति (परिया 75 वर्ग यार्ड, खसरा नं.35) इदबस्तन गाँव शाहबेरी, परगना एवं तहसील वादरी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, ७०५० जो श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी कृष्ण कुमार के नाम में सम्पत्ति जो घिरा है: पूर्व: 22 फीट चौड़ी रोड पश्चिम: अन्य सम्पत्ति उत्तर: रमेश्वरी का प्लॉट दक्षिण: अन्य सम्पत्ति	03.06.2019	14.10.2019	₹. 20,56,117/- और उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार/व्यय।
<b>कर्जदारों का ब्याज प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को घुड़ाने के लिए उपलब्ध समग्र के संवय में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।</b>					
<b>स्थान: गाजियाबाद / गौतमबुद्ध नगर</b>					
<b>दिनांक: 14.10.2019</b>					
<b>प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</b>					

### दिल्ली का रण

## केजरीवाल चुनाव जीतने की रणनीति पर कर रहे काम

मनोज मिश्र  
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाना भी बंद कर दिया है। इसी का असर रहा कि उन्होंने अपने पहले के बयान को पलटते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन किया। हर बात पर नौकरशाही और उपराज्यपाल से भिड़ते रहने वाले केजरीवाल

मई के लोकसभा चुनाव के बाद एक भी बयान नौकरशाही के खिलाफ नहीं दिया। उनकी बड़ी मुफ्त घोषणाओं में महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है। डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा तो शुरू भी होने वाली है लेकिन मेट्रो पर विवाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एतराज करते हुए कहा कि वह जनता के पैसे का दुरुपयोग होने पर दर्शक बना नहीं रह सकता है। बावजूद इसके केजरीवाल ने घोषणा से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। पिछली घोषणाओं से आगे जाकर केजरीवाल ने बिजली-पानी में पहले से ज्यादा मुफ्त करने, अनधिकृत कॉलोनीयों को नियमित करने के साथ-साथ उनमें रजिस्ट्री शुरू करने, पूर्वांचल (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि के मूल निवासियों) के प्रवासियों को अपने पक्ष में स्थायी करने के लिए दिल्ली के स्कूलों में मैथिली की पढ़ाई

शुरू करवाने और भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के प्रयास आदि अनेक घोषणाओं की शृंखला खड़ी कर दी है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाओं-गढ़वाली और कुमाऊंकी अकादमी बनाने की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक घोषणाओं के साथ साथ उन्हें मुफ्त तीर्थ यात्रा का अभियान सरकार काफी दिनों से चला रही है। युवाओं के लिए पहले से ही उच्च शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर कर्ज के अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों को फीस सरकार से भरवाने की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा चार नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण रोकने के नाम पर कारों के लिए सम-विषम योजना लागू करेगी। उसमें पर्यावरण अनुकूल सीएनजी से चलने वाली कारों को तो छूट नहीं है। महिला के चलाने वाली कारों को 12 साल के बच्चे के साथ छूट दी गई है। कारों से कई गुणा ज्यादा संख्या

वाली दो पहिया वाहनों को छूट इसलिए दी गई है कि जो वर्ग दो पहिया चलाता है, उसी को आप अपना बनाना चाहती है। सड़कों पर सार्वजनिक वाहन न होने से सम-विषम में कार चालकों को परेशानी होगी लेकिन माना जा रहा है कि इससे 'आप' का मतदाता कम प्रभावित होगा। केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए अपना लक्ष्य तय रखा है, उन्हें पता है कि सार्वजनिक कामों का असर कम होता है इसलिए उनकी सरकार ने सीधे लोगों को लाभ देना शुरू किया है। जो वे घोषणा करते हैं उसके बड़े-बड़े विज्ञापन प्रभावशाली मीडिया में दिए जाते हैं। तभी तो एक हजार बसों की घोषणा के बाद महज 25 एक्सप्रेस बसें सड़कों पर आईं और कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और डीटीसी आदि में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने से लेकर पांच साल के लिए की गई घोषणाओं पर कोई बहस नहीं चलाई गई।



## बुद्धा सर्किट के यात्रियों के खानपान का खा जाएगा विशेष ध्यान

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर ।

रेलवे भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की छोटी-छोटी खानपान की जरूरतों का ध्यान रखेगा। इसके लिए ट्रेन में विशेषतौर पर विशेष पेंटीकार और दो डार्चनिंग टेबल का इंतजाम किया गया है। आइ आरसीटी के मुताबिक यात्रा के लिए 50 फीसद सीट भर चुकी है। इन यात्रियों के साथ ट्रेन आज रवाना होगी। शुक्रवार को रेलवे ने खास सुविधाओं के साथ तैयार की गई इस ट्रेन का मीडिया ट्रायल किया।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सफर में खानपान लोगों की पहली पसंद होती है। इसका विशेष ध्यान ट्रेन में रखा जाएगा। धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्री प्याज-लहसुन जैसी सब्जियों से भी परहेज करते हैं। यात्री अगर रेलवे अधिकारियों से खानपान में इन चीजों का प्रयोग नहीं करने का आग्रह करेंगे तो उनके लिए स्वादानुसार ही भोजन परीसा जाएगा। आज देर शाम यह ट्रेन रवाना होगी और 26 अक्टूबर तक भ्रमण चलेगा। यह दूर पैकेज इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइ आरसीटीसी) ने तैयार किया है। इस सफर के लिए एक दंपती को प्रथम श्रेणी के लिए 1,23,900 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि एसी 2 में प्रति दंपती भुगतान 1,01,430 रुपए होगा। पैकेज में यात्रियों को भगवान बुद्ध के जन्मस्थली से लेकर उनके जीवनकाल से जुड़े हर स्थल तक ले जाया जाएगा।

## चार वायुसेना कर्मियों की हत्या मामले में जेकेएलएफ का पूर्व आतंकी गिरफ्तार

जम्मू, 18 अक्टूबर (भाषा) ।

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व आतंकवादी जावेद अहमद मीर उर्फ जावेद नलका को 1990 में एक स्कॉड्सन लीडर सहित वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या करने के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया। हालांकि, बाद में अदालत ने उसे जमानत दे दी। यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने दी।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मीर की गिरफ्तारी की गई और उसी दिन उसे सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। मीर 1980 के दशक में आतंकवाद से जुड़ने से पहले कश्मीर में जलकल विभाग में कार्य करता था और वहीं से उसके नाम के साथ ‘नलका’ जुड़ा। अधिकारी के मुताबिक 25

जनवरी, 1990 को श्रीनगर के रावलपोरा में हुए आतंकी हमले में स्कॉड्सन लीडर रवि खन्ना सहित वायुसेना के चार कर्मी शहीद हो गए थे और एक महिला सहित करीब 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मीर का नाम जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक सहित अन्य के साथ आरोपी के रूप में दर्ज है।

मलिक अभी न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने मलिक, मीर और चार अन्य के खिलाफ मामले में जम्मू की आतंकवाद निरोधी अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने पर 1995 में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की फैकल पीठ ने रोक लगा दी थी। 2008 में मलिक ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मुकदमे को श्रीनगर स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया।

# चिन्मयानंद प्रकरण : पीड़िता को बरेली में एलएलएम में दाखिला मिला

शाहजहांपुर, 18 अक्टूबर (भाषा) ।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद पीड़िता को अदालत के आदेश पर शुक्रवार को सुबह बरेली कॉलेज में एलएलएम में दाखिले के लिए ले जाया गया। इस युवती ने ही चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। बाद में मिली जानकारी के अनुसार, बरेली के विश्वविद्यालय परिसर में एलएलएम में पीड़िता के दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई।

महात्मा ज्योति फुले विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अमित सिंह ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर से पुलिस सुरक्षा में लाई गई पीड़िता के परीक्षा फार्म, लाइब्रेरी फार्म सहित दाखिले की प्रक्रिया सुबह करीब नौ बजे पूरी की गई और दाखिला शुल्क भी जमा कर लिया गया है।

पीड़िता स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में एलएलएम की छात्रा है। उसने एक वीडियो के जरिए स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महात्मा ज्योतिवा

## अनूप कुमार सिंह एनएसजी के नए प्रमुख

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) ।

गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

शुक्रवार को आए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1985 बैच के आइपीएस अधिकारी सिंह की ‘ब्लैक कैट्स कमांडो’ बल के डीजी के तौर पर नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है।

यह पद तेलंगाना कैडर के 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी सुदीप लखटकिया की सेवानिवृत्ति के बाद पिछले दो महीने से खाली पड़ा था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘यह नियुक्ति पद संभालने की तारीख से 30 सितंबर 2020 तक या अगले आदेश तक होगी।’

फुले विश्वविद्यालय में एलएलएम में पीड़िता के दाखिले का आदेश दिया था। परंतु दाखिले से पहले ही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पीड़िता को जेल भेज दिया था।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

महात्मा ज्योति फुले विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अमित सिंह ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर से पुलिस सुरक्षा में लाई गई पीड़िता के परीक्षा फार्म, लाइब्रेरी फार्म सहित दाखिले की प्रक्रिया सुबह करीब नौ बजे पूरी की गई और दाखिला शुल्क भी जमा कर लिया गया है।

(सीजेएम) ओमवीर सिंह की अदालत से एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर अदालत ने 18 अक्टूबर को पीड़िता का बरेली कॉलेज में एलएलएम में दाखिला कराने का आदेश दिया था।

पुलिस अधीक्षक डॉ एस चिनप्पा ने शुक्रवार को बताया कि सीजेएम के आदेश पर जेल प्रशासन ने पीड़िता को बरेली ले जाने के

लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। इसके बाद पुलिस का एक दल पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर बरेली कालेज गया।

जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि शुक्रवार सुबह लुगभग सात बजे पीड़िता को दाखिले के लिए बरेली कॉलेज भेजा गया। स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 24 अप्रस्त को एक वीडियो वायरल कर पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओमवीर सिंह ने यहां शहर कोतवाली में पीड़िता के खिलाफ रंगदारी मांगने का एक मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं दूसरी ओर पीड़िता के आरोपों और चिन्मयानंद का मालिश कराते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विशेष जांच दल ने चिन्मयानंद को आरोपी बनाते हुए धारा 376 सी के तहत उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में चिन्मयानंद समेत पांच आरोपी जेल में बंद है। मामले की जांच एसआइटी कर रही है। एसआइटी को अपनी जांच रिपोर्ट 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ को सौंपनी है।

## तलाक के खिलाफ बच्चों के करतार सिंह भड़ाना साथ धरने पर बैठी महिला

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर ।

हरियाणा के रहने वाले गुर्जर नेता और पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया।

बार-बार दल बदलने वाले भड़ाना बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वे पहले भी भाजपा में रह चुके हैं। वे कांग्रेस नेता अवतार सिंह भड़ाना के भाई हैं और उनके परिवार का खासतौर से गुर्जर समुदाय में काफी प्रभाव है।

करतार सिंह भड़ाना दो बार हरियाणा से और एक बार उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं हरियाणा में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और मर्तों को गिनती 24 अक्टूबर को होगी।

## अमिताभ बच्चन को जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

मुंबई, 18 अक्टूबर (भाषा) ।

अमिताभ बच्चन को नियमित जांच के लिए भर्ती कराए गए मुंबई के नानावती अस्पताल से एक या दो दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अस्पताल के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बच्चन के लीवर की समस्या से पीड़ित होने की खबरें चल रही हैं लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चन 11 अक्टूबर को 77 वर्ष के हुए हैं। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया, ‘बच्चन नियमित जांच के लिए मंगलवार को अस्पताल आए थे। लीवर समस्या और इस संबंध में चल रही अन्य खबरें सच नहीं हैं। वह तंदुरुस्त और जोश में हैं। उन्हें एक या दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। परिवार ने निजात बरतने का अनुरोध किया है।

पत्नीजायत्री/गई दिल्ली विविचन फेडरल टॉवर, कर्फी भूमि उद, 2/2, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-4०733980, 40733978	<b>फेडरल बैंक</b> <small>आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भगीनार</small>
---	---

सर्वेकी अधिनियम, 2002 की धारा 13(२) (एच के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ प्रविष्ट प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना.

(1) श्री ब्रिज मोहन बिन्दल पुत्र श्री जसवंत बिन्दल (2) श्रीमती अजलि बिन्दल पत्नी श्री ब्रिज मोहन बिन्दल (3) श्री कुनाल बिन्दल पुत्र श्री ब्रिज मोहन बिन्दल सभी निवासी नवान नं. 151, ब्लॉक-सी, मधुवन, विकास मार्ग, गंग नरहापती, फाजलपुर, नई दिल्ली-110092 इसके साथ-साथै मैट्रेस इंडिया प्रा. लि., 207-208, चौपड़ा कॉम्प्लेक्स, सुसर तल, 8, कान्चुनिटी स्टेट, श्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

आप प्रथम में प्रधान कर्जदार और द्वितीय एवं तृतीय ने सह-कर्जदार / गारंटर के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा समग्रियों / ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के बाद हमारे बैंक की निर्माण विहार गण्डा जे ओडिटेड युक्तिक के तौर पर ऋण लिया । बैंक से उपरोक्त क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के एवज में सुरक्षा के तौर पर श्री ब्रिज मोहन बिन्दल ने 31.03.2015 को सुरक्षा जमा के तौर पर निम्नलिखित कयल सम्पत्तियों को बैंक के पास बंधक रखकर बैंक के पक्ष में सुरक्षा ब्याज का सृजन किया।

**बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण**
दिल्ली अधीकरारों को-ओप, हाउस विन्डिंग रोसाइटी लि, कोवली को मधुवन के रूप में जाना जाता है, गांव भंडावली का एरिया, फाजलपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092 के नोकराघाट प्लान नं प्लॉट नं. 151, परिवारा 330 वर्ग गार्ड के सभी भाग एण हिस्सों की साथ उस पर वर्तमान और / या निर्मित किये गये सभी भवन जो विरा हे पूर में प्लॉट नं 150, परिवहन में प्लॉट नं. 152, उत्तर में गंज 45 फीट चौड़ी एच दक्षिण में ६0 फीट चौड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क ।

उपरोक्त वर्णित देनकर्ता / बंधककर्ता सम्पत्तियों को यहां के बाद ‘प्रतिभूत परिसम्पत्तिया’ कहा गया है। अथोहत्ताहरी फेडरल बैंक लि के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर एनद्दहार सुविधा करते है कि हमारे बैंक की निर्माण विहार शाखा नं 30.09.2019 को आपके धोपटी भावर लोन 14515600009948 में रु. 1,29,६8,229 /- (एक करोड़ उन्नीस लाख अठसठ हजार दो सौ उन्नीस रुपए) और धोपटी भावर लोन 14515600001128 में रु.27,4६,347 /- (सातसठ लाख पचासीस हजार तीन सौ तीसतीस रुपए) अर्थात् कुल रु.1,57,1४,57६ /- की राशि आपके पास सजुकर या अलग-अलग रूप से बकाया है । मुनमुस्ताम में चूक को देखते हुए आपके ऋण खाते को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन परफार्मिंग एंस्ट्रन के रूप में वर्गीकृत है । एतद्दहार आपकी इस सूचना की तिथि से ६0 दिनों के भीतर धोपटी भावर लोन 14515600009948 कगिन राशि और 01.10.2019 से उवा पर मासिक रूप से शेष के साथ 1२.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दलन भुगतान एवं सातत की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बैंकब ब्याज और प्रोपटी भावर लोन 14515600001128कगिन राशि और उवा पर मासिक रूप से शेष के साथ 12.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दलन भुगतान एवं सातत की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बैंकब ब्याज और प्रोपटी भावर लोन 14515600001128कगिन राशि और उवा पर मासिक रूप से शेष के साथ 1२.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दलन भुगतान एवं सातत की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बैंक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको आगे कोई और सुचना दिये अल्पन बकायों की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को लोन पर देने या अनुबंध पर देने या किसी या इनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने सहित संपरोक्त वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगा। अाएं आपका सुचित किया जाता है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति के उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को लोन पर देने या किसी या कोई अन्य लेनदेन नहीं करेंगे और कोई भी गैरकानूनी कार्य करने पर बैंक की तरफ से उचित कानूनी कार्रवाही की जाएगी और इस संबंध में बैंक की सभी लागत, प्रभाए एवं ब्याज का भुगतान भी आपको करना होगा। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की किसी पर भी पूरी विधि शर्तों प्राण नहीं होती है तो बैंक बिना कोई सूचना दिये शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाही करेगा। प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) के निचेमान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(६) के प्रावधानों को अाए अावृष्ट किया जाता है। यह सूचना बिना किसी ब्याजह के अलग के बकायों की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य अधिकार एव साथ के अगता जारी की जाती है। यह सूचना 3 अक्टूबर, 2019 को जारी की गई थी और इसे आपके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया इसलिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अनुसार इसे अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है।

**डू को फेडरल बैंक लिमिटेड, सहायक सहायक (सर्वेकी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी**

सर्किल कार्यालय: बुलन्दशहर

पता: यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.–203001

मो.: 9897912444, फोन: 05732-281724, ईमेल: [cobrsamd@pnb.co.in](mailto:cobrsamd@pnb.co.in)

## पंजाब नैशनाल बैंक Punjab national bank ..the name you can BANK upon!

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ४ एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की विक्री के लिये ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ४(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टेजिजों/ गारन्ट्रों को सुचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई, चार्जड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्ट्रों/ मार्टेजिजों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया नीचे वर्णित ऋणों की वसूली के लिये ‘‘जैसा है जहां है; ‘‘ जो भी जैसा है’’ तथा ‘‘जो कुछ भी वहां है’’ आधार पर 13.11.2019 को विक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है। विक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) <https://www.pnbindia.in>, 2) <https://www.pnbindia.biz>, 3) <https://eprocure.gov.in/epublish/app> देखें।

ई-नीलामी की अनुसूची

निरिक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
08.11.2019 (शुक्रवार) 12.00 बजे अप. से 16.00 बजे अप.	11.11.2019 (सोमवार) 16.00 बजे अप. तक	13.11.2019 (बुधवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/मार्टेजिजों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	सर्वेकी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सर्वेकी अधिनियम की धारा 1३(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	मै. श्री कान्हेगोदर-प्रां. श्रीमती सीमा सोलंकी शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान, श्री उत्कोच चौहान	रु. 7950872/- के साथ 1.7.2018 से आगे का ब्याज	गली नं. 2, गुलर रोड, अलीगढ़ में स्थित आवासीय मकान सं. 5/117, माप 200.00 वर्ग यार्ड्स, चौहड़ी: उत्तर पुष्पा देवी का मकान, दक्षिण: जय नारायण का मकान, पूर्व: चाम्बे खाला पेच, पश्चिम: 8 फीट चौड़ा रास्ता	रु. 5000000/- (रु. पचास लाख मात्र)	रु. 5000000/- (रु. पांच लाख मात्र)	1.8.2018	10.01.2019 (संकेतिक कब्जा)
2.	मै. यूटुक पैकेजिंग, प्रां. श्रीमती प्रत्यूष प्रभा, पत्नी श्री संकोच चौहान शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	प्रत्यूष प्रभा एवं सीमा सोलंकी	रु. 5092342/- के साथ 1.7.2018 से आगे का ब्याज एवं लागत	‘‘प्लॉट नं. 79५, 79 थो, 80, 81, ब्लॉक सी, चसंत विहार कोलोनీ, खसरा नं. 49, अलापुर गाँइया, खैर बाईपास रोड, पी एंड टी कोहल, अलीगढ़, उ.प्र.–202001, एरिया माप 340.71/ वर्ग मीटर, चौहड़ी: उत्तर: संकोच चौहान की सम्पत्ति, पश्चिम: रोड 14 फीट चौड़ा, पूर्व: सोसायटी के सदस्य का प्लांट, पश्चिम: रोड 23'0’’ चौड़ दिग्भूमि: ईएम, विक्री प्रलेख की प्रमाणित प्रति के आधार पर की गई, मूल टाइटल डीड बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।	रु. 1800000/- (रु. अठारह लाख मात्र)	रु. 1800000/- (रुपये एक लाख अरसी हजार मात्र)	14.09.18	10.01.2019 (संकेतिक कब्जा)
3.	मै. गगन बुक डिपो-प्रां. श्री उमा शंकर, पुत्र श्री राम चन्द शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सुधा शर्मा, पत्नी श्री उमाशंकर शर्मा	रु. 1371706.33/- के साथ 1.1.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	एच नं. 19/196, गगन बुक डिपो, बापू नगर, खेत नं. 303, गम्भीरपुरा, गली नं. 2, मनोई हिसा के निकट, परगणा एवं तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उ.प्र.–202001, में स्थित आवासीय मकान, माप 62.70 वर्ग मीटर। चौहड़ी: पूर्व: प्रेमपाल का मकान, पश्चिम: 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: संतोष कुमार का मकान तथा दक्षिण: राजेन्द्र का मकान	रु. 1600000/- (रुपये सोलह लाख मात्र)	रु. 1600000/- (रुपये एक लाख सठ हजार मात्र)	29.01.2018	27.8.2018 (संकेतिक कब्जा) * अब, बैंक के पास भौतिक कब्जा है।
4.	मै. तनिक र्टील शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 38.03,128/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र. में स्थित औद्योगिक प्लांट एन. 29 से 32, माप 512 वर्ग मी. चौहड़ी: पूर्व: इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, पश्चिम: प्लांट नं. 35, 36, 37 एवं 38, उत्तर: प्लांट नं. 3, दक्षिण: प्लांट नं. 38	रु. 14000000/- (रु. चौदह लाख मात्र)	रु. 14000000/- (रु. एक लाख चालीस हजार मात्र)	3.5.2018	24.7.2018 (संकेतिक कब्जा)
5.	श्री कमलेश चन्द गुप्ता शाखा: विक्रम कॉलोनी, अलीगढ़	श्री कमलेश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रश्मि गुप्ता	रु. 8079399/- के साथ 1.5.18 से आगे का ब्याज	मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र. में स्थित औद्योगिक प्लांट एन. 29 से 32, माप 512 वर्ग मी. चौहड़ी: पूर्व: इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, उ. प्र.–2015 को क्रम सं. 89६6 पर यहाँ नं. 1, जिनन्दन, 12130, पेज 303/348 पर सब-रजिस्ट्रार कोर्टल के पास पंजीकृत आवासीय प्लैट नं. 4, प्रथम तल, स्वयंभू टावर, जापान हाउस, मैरिस रोड, अलीगढ़ उ.प्र.–202001, माप 153.28 वर्ग मीटर, चौहड़ी: पूर्व- खुला स्थान बाउण्ड्री वाल कॉम्प्लेक्स, पश्चिम: प्रवेश लॉबी, सड़ियाँ, उत्तर: खुला स्थान बाउण्ड्री वाल कॉम्प्लेक्स, दक्षिण: अमित कुमार अग्रवाल का प्लैट नं. 5	रु. 38,90,000/- (रु. अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 3,89,000/- (रु. तीन लाख नवासी हजार मात्र)	7.6.2018	10.10.2018 (संकेतिक कब्जा)
6.	मै. मा वैष्णो कॉन्गिदर-प्रां. श्री संकोच चौहान, शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 9425423/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	खसरा नं. 49, प्लैट नं. 93, 94, 92, ब्लॉक सी, अलापुर गाँइया, परगणा एवं तहसील कोइल, अलीगढ़, उ.प्र.–202138, माप 310.81 वर्ग मी. में स्थित फेक्ट्री भूमि एवं भवन	रु. 27,00,000/- (रु. सत्ताईस लाख मात्र)	रु. 2700000/- (रु. दो लाख सत्तर हजार मात्र)	21.4.2018	12.7.2018 (संकेतिक कब्जा)
7.	श्री उत्कोच चौहान शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री उत्कोच चौहान	रु. 7553005/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	बुक नं. 1, वॉल नं. 7702, पेज 345/3676, एसएन 7624 तिथि 31.7.15 में सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत पूरा भवन, दिल्ली गेट, गुलर रोड, अलीगढ़, उ.प्र.–202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 108.50 वर्ग यार्ड्स। चौहड़ी: पूर्व: राजेश कुमार की सम्पत्ति, पश्चिम: शैलेंद्र कुमार की सम्पत्ति, उत्तर: 19 फीट चौड़ा पैलेज, दक्षिण: अन्य का मकान।	रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र)	रु. 5000000/- (रु. पांच लाख मात्र)	18.4.2018	3.7.2019 (भौतिक कब्जा)
8.	श्री संकोच चौहान शाखा: एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 7347878.14 के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	10/11, सूर्य भवन, दिल्ली गेट, गुलर रोड, अलीगढ़, उ.प्र.– 202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 99.66 वर्ग यार्ड्स, चौहड़ी: पू: विक्रेता की भूमि, अब उत्कोच चौहान का मकान, प.-योगेश जोहरी की सम्पत्ति, उ.– 19 फीट चौड़ा पैलेज, द.-चेतराम का मकान	रु. 45,00,000/- (रु. पैंतालिस लाख मात्र)	रु. 4500000/- (रु. चार लाख पचास हजार मात्र)	18.4.2018	3.7.2019 (भौतिक कब्जा)

ई-नीलामी विक्री के नियम एवं शर्तें

- सम्पत्ति की विक्री ‘‘जैसा है जहाँ है आधार’’ तथा जो भी वहाँ है आधार’’ पर की जायेगी।
- यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत-विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
- प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
- नीलामी विक्री पोर्टल <https://etender.pnbnet.in>; [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in); [www.eprocure.gov.in/app](http://www.eprocure.gov.in/app) पर ‘‘ई-नीलामी के द्वारा ऑन लाइन’’ होगा।
- बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी विक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल <https://etender.pnbnet.in>; [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in); [www.eprocure.gov.in/app](http://www.eprocure.gov.in/app) देखें एवं/अथवा श्री सुशील कुमार मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8171113784) से सम्पर्क करें।
- इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ‘‘प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक’’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अघोषितखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनर्स्फुटटी/आरटीजीएस द्वारा भुण्डित की जा भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को-अडिरेरिज बैंक का नहीं होना चाहिये।
- ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अघोषितखित जमा करना होगा: 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (‘‘यदि एनर्स्फुटटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (\* यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) 2. आईटी डूफ अर्थात् पेन काई आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय प्लैट (प.पता, 4. क) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. (प.पता, ५) ई-मेल बोली’’ के रूप में शोषितखित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पत्र पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व-सांघ्यपित हाई कॉपी भी जमा करना होगा।
- इच्छुक बोलीदाता को मुख्य प्रबंधक, श्री राजवीर सिंह (मो.नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम बुलन्दशहर, उ.प्र.–203001 से सन्धि में लातिन बोलीदाता तथा गार्वरड भी प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिये अनिवार्य है। यह लातिन आईटी तथा गार्वरड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल के पत्र पर भेजा जायेगा। यदि यह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो उपरोक्त अनिवार्यता से सम्पर्क करें।
- केवल वैध युजर आईडी एवं पासवर्ड तथा एनर्स्फुटटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नी



# जनसत्ता

## अमीरी का आंकड़ा

**भारत** में बड़े अमीरों की संपत्ति बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, यह सुन कर गरीबों को थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में अमीर जिस तेजी से और अमीर हुए हैं और गरीबों की गरीबी और ज्यादा बढ़ी है, यह हैरान करने वाला तथ्य है। जाहिर है, असमानता कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अमीर-गरीब के बीच खाई और चौड़ी हुई है, यह एक प्रामाणिक सच्चाई है। ऐसे में समतामूलक समाज की कल्पना तो नहीं की जा सकती! देश में गरीब और मध्यम वर्ग का तबका सबसे बड़ा है और यही असल गरीब भी है। अरबपतियों की तादाद तो सिर्फ कुछ लाख ही है। इसलिए ऐसे में जब अरबपतियों की संख्या बढ़ने-घटने या उनकी संपत्ति में कमी-बेशी होने की खबरें आती हैं, तभी गरीब को इनकी भनक लगती है। हाल में धन प्रबंधन का आकलन करने वाली एक संस्था कार्वा वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल अमीरों की संपत्ति वृद्धि की दर घट कर 9.62 फीसद रह गई है जो पूर्ववर्ती वर्ष (2017) में साढ़े तेरह फीसद थी। अमीरों की संख्या भी घटी है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में अरबपतियों की संख्या दो लाख तिरसठ हजार से घट कर दो लाख छपन हजार रह गई, यानी सात हजार लोग अरबपति से करोड़पति की श्रेणी में आ गए। इसलिए एक सवाल यह भी उठता ही है कि अमीर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी संपत्ति में गिरावट आ रही है और अरबपति की श्रेणी से बाहर हो रहा है।

सवाल है कि अमीर या बड़ा अमीर है कौन। मोटे तौर पर अमीर वही है जो हर तरह के आर्थिक संसाधनों से संपन्न है, जिसके पास खासी संपत्ति हो, उद्योग-धंधों, निवेश, विदेश व्यापार जैसी गतिविधियों में उसकी भागीदारी हो। करोड़पति भी अमीर ही हैं, लेकिन इनकी संख्या कुछ करोड़ों में ही होगी। मध्यवर्ग और निम्न वर्ग ही हैं जिन्हें रोजगार की समस्या से सबसे ज्यादा रूबरू होना पड़ रहा है। लोगों के पास काम के अवसर सीमित होते जा रहे हैं और इसलिए इनमें भी एक बड़ा तबका ऐसा बनता जा रहा है जो आज पंद्रह-बीस हजार की नौकरी करने के लिए मजबूर है। जाहिर है, ऐसे में निम्न आय वर्ग का तबका और बड़ा होता जाएगा। पर अमीरों पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि यह वर्ग करोड़पति और अरबपति के बीच ही बना रहेगा।

अगर बड़े अमीरों की तादाद घट रही है तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जिसे अमीरों पर असर पड़ रहा है। पर आमजन तो यही सोचता है कि अगर अमीर के पास से पैसा निकल रहा है तो वह गरीब को क्यों नहीं मिल रहा! संपत्ति के लिहाज से देखें तो भारत के अमीरों के पास मौजूद कुल संपत्तियों में दो सौ बासठ लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्ति है। इनकी चल-अचल संपत्ति का अनुपात साठ-चालीस का है। इस तरह की खबरें हैरान इसलिए करती हैं कि ये अमीरी के आंकड़े और इनकी गाथा उस देश में है जो भुखमरी से निपट पाने के मामले में वैश्विक पैमाने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे है। जहां आज भी करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, आवादी का बड़ा हिस्सा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, बच्चों को शिक्षा के अवसर वैसे नहीं हैं जो मिलने चाहिए। ग्रामीण भारत की हालत तो आज भी चिंताजनक है। ऐसे में भारत पांच लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। अमीर अपनी घटती दौलत से परेशान हैं। ऐसे में गरीब की चिंता करने वाला कौन है?

## संवेदनहीनता की हद

मध्यप्रदेश में ग्वालियर जिले के समूदन गांव में आवारा घूम रही आठ गायों सहित सत्रह गोवंश की मौत जिस तरह हुई, हो सकता है उसे कुछ पशुओं की मौत मान कर लोग बाकी का काम बिना किसी परेशानी के करने लगें। लेकिन इंसानी समाज अपने विकास के साथ आज जिस मुकाम तक पहुंच सका है, वहां यह उम्मीद होगी कि लोगों के भीतर किसी भी जीव के प्रति संवेदना के तत्त्व जिंदा रहें। सवाल है कि जो पशु न केवल आम जीवन, बल्कि उपयोगिता के लिहाज से भी मानव समाज के साथी रहे हैं, लोग उनको देखरेख के लिए तन-मन-धन से समर्पित रहे हैं, आज उनके आवारा घूमने की नौबत कैसे आ गई है! गौरतलब है कि ये पशु आमतौर पर निजी स्वामित्व से लेकर गोशालाओं के संरक्षण में पलते रहे हैं और उनकी देखभाल का एक समूचा सामाजिक तंत्र बना रहा है। लेकिन समूदन गांव के आसपास ये पशु आवारा घूम रहे थे और कुछ लोगों ने स्थानीय सरकारी स्कूल के एक कमरे में उन्हें दूंस कर बंद कर दिया। उस कमरे में वे पशु पिछले सात दिन से बिना चारा-पानी के बंद थे और आखिर उनमें से सत्रह की जान चली गई।

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब दोषियों की खोज की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां गाय एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बेहद संवेदनशील पशु के तौर पर देखी जाने लगी है, वहीं इतनी सारी गायें बिना किसी संरक्षण के आवारा घूमने की हालत में हैं और कुछ लोगों की ऐसी क्रूरता की शिकार बन रही हैं। हाल में ऐसी खबरें जरूर आई हैं कि आवारा पशुओं की वजह से कई इलाकों में खेतों में लगी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गाय या बैल जैसे पशु अब तक सामाजिक जिम्मेदारी रहे हैं, उनके पालन-पोषण से लेकर अंतिम समय तक के लिए एक समूचा चक्र बना हुआ है और पशुपालन के काम में लगे लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर कई बार बेहद भावुक भी रहे हैं। लेकिन आज यह देखना विचित्र है कि कुछ लोग पशुओं के खिलाफ इस हद तक बेरहम हो जा रहे हैं।

हमारे समाज में सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होने की सीख दी जाती रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के तहत भी यह कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कई कानून भी मौजूद हैं। लेकिन इन पहलुओं की अनदेखी करके आज पशुओं के प्रति ऐसे बर्ताव करते हुए लोग नहीं हिचक रहे हैं। अक्सर सड़कों पर गुजर रहे वाहनों में गाय-बैस या दूसरे पशुओं को बेहद तकलीफदेह हालात में ले जाते देखा जा सकता है। कई बार आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या की शिकायतों के बाद संबंधित प्रशासनिक महकमे के लोग जिस तरह उन्हें वाहनों में भर कर ले जाते हैं, वह मनुष्य की संवेदना पर एक सवालिया निशान की तरह होता है। जबकि पशुओं को असुविधा में रख कर, दर्द पहुंचा कर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक से दूसरी जगह ले जाना दंडनीय अपराध भी है। सभ्य समाजों का हिस्सा होने के नाते मनुष्य से इस तरह की संवेदनहीनता की अपेक्षा कतई नहीं होती है। ईंसान और पशु की जगह अलग-अलग हो सकती है। लेकिन इंसान से यह उम्मीद जरूर होगी कि कम से कम वह अपनी इंसानियत ही बचा ले!

## कल्मषेधा

**अमीर और गरीब के अंतर कितना मामूली है!**

**एक ही दिन की भूख और प्यास दोनों**

**को बराबर बना देती है।**

**-खलील जिब्रान**

**ब्रह्मदीप अलूने**

**तुर्की में इस समय बीस फीसद कुर्द हैं। पीढ़ियों से तुर्की में कुर्दों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता रहा है। तुर्की में कुर्दिश नाम और उनके रिवाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुर्दिश भाषा भी प्रतिबंधित है। यहां तक कि कुर्दिश पहचान को भी खत्म कर दिया गया है। साल 2017 में इराक में अलग कुर्दिस्तान के लिए जनमत संग्रह हुआ तो भारी तादाद में कुर्दों ने इसके पक्ष में मत डाले। इसके बाद तुर्की कुर्दों को लेकर गहरे दबाव में आ गया।**

**ब**गावत और हिंसक संघर्षों से लंबे समय से जूझते देश सीरिया की आंतरिक राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। इस्लामिक स्टेट ( आइएस) के खूनी संघर्ष से निपटने में सीरिया के मददगार रहे तुर्की के तेवर अचानक बदल गए हैं। दरअसल, कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को सीरिया की जंग से अलग करने का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही तुर्की ने कुर्दों को निशाना बना कर पश्चिम एशिया में नया संकट खड़ा कर दिया है। तुर्की कुर्दों के संगठन को आतंकवादी समूह मानता है और उसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताता रहा है। वहीं, अमेरिका कुर्दों को लेकर उदार रवैया दिखाता रहा है। पश्चिम एशिया की मुसलिम लड़ाकू जनजाति कुर्द अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इसका प्रभाव सीरिया के उत्तरी इलाकों के साथ ही तुर्की, इराक और ईरान तक है। सीरिया के उत्तर में कुर्द टिकानों पर तुर्की की सेना

# मध्य-पूर्व में कुर्दिस्तान की आहट

लगातार गोलाबारी कर रही है और इससे इस इलाके में रहने वाले हजारों परिवार युद्ध की मार झेल रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में शुमार इस क्षेत्र में आइएस के कई लड़ाके कुर्दों के कब्जे में हैं और तुर्की के हमलों के बाद से वे जेलों से भाग रहे हैं। आइएस के इन खूंखार लड़ाकों को कुर्दों ने अमेरिकी सेना की मदद से बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। ऐसे में इनका भाग निकलना पश्चिम एशिया सहित पूरी दुनिया को खतरें में डाल सकता है। यदि ये लड़ाके फिर से संगठित हो गए तो आइएस मध्य-पूर्व में फिर से मजबूत हो जाएगा और इसके दूरगामी परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। दूसरी ओर, तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दों पर हमले के अमेरिका और यूरोप के विरोध को दरकिनार कर धमका रहे हैं कि यदि उन्हें हमलों से रोका गया तो वे पश्चिमी एशिया के छत्तीस लाख युद्ध प्रभावित शरणार्थियों को यूरोप में धकेल देंगे।

तुर्की का कहना है कि सीरिया से गृह युद्ध के चलते जो शरणार्थी तुर्की में रहे रहे हैं, उन्हें वे सुरक्षित क्षेत्र में बसाना चाहते हैं। वह वहां बीस लाख सीरियाई शरणार्थियों के लिए एक शिविर बनाएगा। फिलहाल यह इलाका कुर्दों के पास है। कुर्द लड़ाकों की मदद कर रही सीरिया सरकार की सेना रणनीतिक रूप से अहम मानबिज शहर में दाखिल हो गई है। तुर्की इस इलाके को खाली करवा कर सुरक्षित क्षेत्र बनाने की बात कह रहा है। इस समूचे घटनाक्रम में अमेरिका की पश्चिम एशिया को लेकर पूर्व से चली आ रही अस्थायी और अस्पष्ट नीति एक बार फिर सामने आई है।

बीते कई सालों से महाशक्तियां मध्य-पूर्व को शतरंज की बिसात पर तोल कर शह और मात का खेल खेलती रही हैं। इसमें तेल की राजनीति के साथ मजबूक की जोर आजमाइश को बढ़ावा दिया गया है। विश्व के संपूर्ण उपलब्ध तेल का लगभग छियासठ प्रतिशत ईरान की खाड़ी के आसपास के इलाकों, मुख्य रूप से कुवैत, ईरान और सऊदी अरब में पाया जाता है। सौविद्यत संघ और अमेरिका तो तेल के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन यदि यूरोप को इस इलाके से तेल मिलना बंद हो जाए तो उसके अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और इस प्रकार यूरोपीय महाद्वीप की औद्योगिक और सामरिक क्षमता बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी देश मध्य-पूर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं।

ईरान को रोकने के लिए अरब राष्ट्रवाद को तोड़ने की जरूरत थी और इसी का परिणाम हुआ कि वर्तमान

में मध्य-पूर्व शिया-सुन्नी के संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। शिया बहुल ईरान की इस्लामिक क्रांति से नाराज अमेरिका ने सुन्नी राष्ट्रवाद की कट्टरता को उभारने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसका असर मध्य-पूर्व के एक महत्त्वपूर्ण देश सीरिया पर भी पड़ा। सीरिया में बहुसंख्यक सुन्नी हैं, जबकि वहां के राष्ट्रपति असद शिया हैं और ईरान समर्थित माने जाते हैं। सीरिया के पूर्व में इराक और उत्तर में तुर्की है। चौहत्तर फीसद सुन्नी आबादी वाले सीरिया में सत्ता अल्पसंख्यक शिया संप्रदाय के बशर अल असद के हाथों में है। उन्हें रूस, अपने पारंपरिक सहयोगी ईरान और ईरान के समर्थन वाले लेबनानी चरमपंथी गुट हिजबुल्ला से मजबूत कूटनीतिक और सैन्य सहयोग मिलता रहा है।

फिर 2011 में जब मशहूर ‘अरब स्प्रिंग’ विरोध प्रदर्शनों ने ट्यूनीशिया और मिस्र में सत्तापलट कर दिया था तो अमेरिका ने इसे असद को सत्ता से बेदखल करने के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा।



सीरिया की सत्ता से असद को हटाने के प्रयास में अमेरिका के मददगार वहां कई विद्रोही संगठन बन गए और इसी बीच आइएस इस इलाके में मजबूती से अपनी पैठ बनाने में सफल हो गया। साल 2013 में अलकायदा से अलग होकर आइएस अस्तित्व में आया और इससे मध्य-पूर्व में संघर्ष का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। आइएस ने अमेरिकी योजनाओं के विपरीत ईसाइयों और उदार मुसलमानों के खिलाफ जेहाद की घोषणा कर मध्य-पूर्व के राजनीतिक संघर्ष की दिशा बदल दी। आइएस ने इस इलाके के तेल कुओं पर अपना कब्जा जमा कर महाशक्तियों के सामने चुनौती पेश कर दी और इसके बाद पश्चिमी देशों, अमेरिका, रूस, तुर्की जैसे देशों ने आइएस को मिल कर खत्म

# विकल्प के रास्ते

लिए इतना खतरनाक बना लेगा। यह ‘सभ्य’ इंसान द्वारा प्लास्टिक उत्पादों से उठाए अनुचित लाभ का उदाहरण है। कुदरत के साथ भी इंसान ने बेहद अनुचित किया।

राष्ट्रीय हरित पंचाट से लेकर देश की कई अदालतें प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के आदेश दे चुकी हैं। कई मामले अदालत में बहस की प्लास्टिक में लिपटे पड़े हैं। लाखों सामाजिक संस्थाएं जुटी हुई हैं, लेकिन कोई प्लास्टिक का विकल्प बताने को राजी नहीं। विकल्प शायद अभी तक उपलब्ध ही नहीं है। कपड़े का थैला, कागज का लिफाफा सीमित विकल्प हैं।

कोई नहीं जानता कि रोज प्रयोग होने वाले दूध के करोड़ों पैकेट की नई पैकिंग कैसे होने वाली है! क्या सुबह से रात तक बिकने वाली पानी की करोड़ों बोतलों की जगह कांच या स्टील की बोतलें लेंगी? सैकड़ों कंपनियों के दर्जनों स्वादों में पैक होकर आने वाले जीभ ललचाऊ, स्वास्थ्य खराब करने वाले चिप्स और दूसरे अनगिनत उत्पाद क्या अब खुले मिलेंगे?

अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ के अनुसार करोड़ों के प्लास्टिक व्यवसाय में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उससे ज्यादा संख्या में पेट यह उद्योग भरता है। इस व्यवसाय से सरकार को मिलने वाला राजस्व भी एक पक्ष है। बेचारी अधिकतर आम जनता

सकी है। यदि समय रहते भारत को भूख की इस समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो यह आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए एक बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करेगा। इस तरह तो तकनीक के कंधे से कंधा मिलाकर चलता भारत और दूसरी तरफ भूख से जंग लड़ता भारत कभी भी एक साथ नहीं आ पाएगा।

- शक्ति प्रताप सिंह, रश्मि खंड, लखनऊ***

**समय की मांग**

एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विकल्प रातोंरात उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, लेकिन इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने की जरूरी हैं। प्लास्टिक के खिलाफ अभियान केवल प्लास्टिक की थैलियों की जगह जूट या कपड़े के थैले या फिर प्लास्टिक के कप के स्थान पर कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आखिर इसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि वर्तमान में खान-पान की लगभग प्रत्येक सामग्री की पैकिंग प्लास्टिक में हो रही है? इसके अलावा दूध भी प्लास्टिक की थैलियों में मिल रहा है। इसे देखते हुए समय की मांग है कि वे कंपनियां भी इस अभियान में योगदान देने के लिए सक्रिय हों जो अपने उत्पादों की पैकिंग प्लास्टिक में करती हैं।

- हेमंत कुमार, गोरार्डीह, भागलपुर, बिहार***

**पराली के पीछे**

धान की फसल काटने के बाद खेतों में बचने वाली पराली को संभालने के संसाधन व मशीनरी महंगी होने

फोन और मनोरंजन में व्यस्त अगले चुनाव तक सरकार का हुक्म बजाने को विश्व है। लेकिन उद्योगपतियों के पास भी एकदम से कोई विकल्प नहीं है। सालों का जमा-जमाया व्यवसाय तुरंत बंद कर नए अपरिचित व्यवसाय के धरातल पर काम शुरू करना बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी छोट्टी से छोट्टी नौकरी तब छोड़ता है, जब उसे नई नौकरी मिल रही हो और उससे आय भी ज्यादा होने वाली हो।

प्लास्टिक बंद करने से पहले जरूरी है कि इस उद्योग में छोटे

से बड़े स्तर तक जितने भी मजदूर, उद्योगपति, व्यवसायी, नौकरीपेशा, दुकानदार और अन्य लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ विस्तार से बातचीत हो, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस आवश्यक सामाजिक बदलाव के लिए नया व्यवसाय अपनाने को तैयार किया जाए। उन्हें समय दिया जाए, ताकि वे अपने और अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी का प्रबंध कर सकें। इस बारे में सरकार उनकी मदद करने के संजीदा प्रयास करे। अभी तक किए गए प्रयास सिर्फ किसी को खुश करने तक सीमित लगते हैं। मान लीजिए दूध के पैकेट का विकल्प कांच की बोतल हो सकती है और प्लास्टिक पाउच बनाने वाली कंपनियां कांच की बोतल बनाना शुरू सकती हैं

के कारण किसान पराली जलाने को मजबूर हो चुके हैं। इस सीजन के दौरान भी पंजाब के किसान पराली को आग ही लगा रहे हैं जिससे न सिर्फ पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है बल्कि खेतों की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो रही है। पंजाब के ज्यादातर किसानों की तरफ से धान की दो किस्में पूर्रा-44 व पीआर-118 समेत बासमती की बिजाई की जाती है और इन किस्में के ज्यादा समय लेने की वजह से इनकी फसल अक्टूबर माह में बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाती है। अक्टूबर के ही चौथे सप्ताह में गेहूँ

की बिजाई का समय शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में किसान धान की

पराली की चौपर से कटाई करने के बाद उसे आग लगा देते हैं जिससे उनका समय व पैसा दोनों बच जाते हैं। हालांकि पंजाब के खेतीबाड़ी विभाग की तरफ से पिछले कई सालों से किसानों को पराली को जलाए बिना ही हैपीसीडर, जीरो ट्रिल ड्रिल, चौपर कम सलेंडर व पेडीबेल्टर के जरिए गेहूँ की बिजाई करने की सलाह दी जाती है लेकिन यह सारी मशीनरी काफी महंगी होने के कारण पंजाब के ज्यादातर किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा विलुप्त हो रही संयुक्त परिवार परंपरा के कारण ज्यादातर किसानों के पास काफी कम जमीन है और वे ऐसी महंगी मशीनरी खरीदना तो दूर, उसे किराये पर लेने की भी क्षमता नहीं रखते। यदि किसान पराली को आग न लगाए तो उसे कम से कम

25 सौ रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा

करने में अपनी भूमिका निभाई। लंबे समय से इस युद्धग्रस्त इलाके से आइएस समाप्त होने की कगार पर आया तो अब एक बार फिर तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल कर नए संकट को जन्म दे दिया है। कभी विरोधी रहे कुर्द सीरिया की असद सरकार से मिल कर दिया का प्रतिरोध कर रहे हैं। वहीं अब रूस भी कुर्दों के समर्थन में आ गया है।

तुर्की से कुर्दों का विरोध पारंपरिक माना जाता है और कुर्द तुर्की को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद पश्चिमी सहयोगी देशों ने 1920 में संधि कर कुर्दों के लिए अलग देश बनाने की बात कही थी। 1923 में तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने इस संधि को खारिज कर दिया था। तुर्की की सेना ने 1920 और 1930 के दशक में कुर्दिश उभार को कुचल दिया था। तब से कुर्दों और तुर्की के बीच दुश्मनी और गहरा गई। तुर्की में इस समय बीस फीसद कुर्द हैं। पीढ़ियों से तुर्की में कुर्दों के साथ

शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता रहा है। तुर्की में कुर्दिश नाम और उनके रिवाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुर्दिश भाषा भी प्रतिबंधित है। यहां तक कि कुर्दिश पहचान को भी खत्म कर दिया गया है। साल 2017 में इराक में अलग कुर्दिस्तान के लिए जनमत संग्रह हुआ तो भारी तादाद में कुर्दों ने इसके पक्ष में मत डाले। इसके बाद तुर्की कुर्दों को लेकर गहरे दबाव में आ गया। उसे डर है कि इस इलाके में कुर्दिस्तान के बनने से उसके देश में बसने वाले कुर्द विद्रोह कर कुर्दिस्तान में मिलने की मांग करेंगे और इससे तुर्की की संप्रभुता पर नया संकट खड़ा हो सकता है।

यूरोप के एकमात्र मुसलिम बहुल देश तुर्की के राष्ट्रपति की मुसलिम शरणार्थियों के नाम पर दी जा रही धमकियों से यूरोप, रूस और अमेरिका चिंतित हैं। ऐसे में सीरिया में संतुलन, ईरान को दबाने और इराक सहित अन्य खाड़ी देशों पर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए मुमकिन है कि आने वाले समय में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अलग कुर्दिस्तान की मांग को मान लें। ऐसा होने पर मध्य-पूर्व का भूगोल एक बार फिर बदल जाएगा और दक्षिणी-पूर्वी तुर्की, उत्तरी-पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर-पूर्वी ईरान और दक्षिण-पश्चिमी अर्मेनिया को मिला कर कुर्दिस्तान अस्तित्व में आ सकता है। कुर्दिस्तान सऊदी अरब और ईरान के प्रभुत्व को खत्म करने का पश्चिमी हथियार बन सकता है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसकी संभावनाएं बलवती हो गई हैं।

के राष्ट्रपति की मुसलिम शरणार्थियों के नाम पर दी जा रही धमकियों से यूरोप, रूस और अमेरिका चिंतित हैं। ऐसे में सीरिया में संतुलन, ईरान को दबाने और इराक सहित अन्य खाड़ी देशों पर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए मुमकिन है कि आने वाले समय में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अलग कुर्दिस्तान की मांग को मान लें। ऐसा होने पर मध्य-पूर्व का भूगोल एक बार फिर बदल जाएगा और दक्षिणी-पूर्वी तुर्की, उत्तरी-पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर-पूर्वी ईरान और दक्षिण-पश्चिमी अर्मेनिया को मिला कर कुर्दिस्तान अस्तित्व में आ सकता है। कुर्दिस्तान सऊदी अरब और ईरान के प्रभुत्व को खत्म करने का पश्चिमी हथियार बन सकता है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसकी संभावनाएं बलवती हो गई हैं।

तो इसमें मानसिक तैयारी, तकनीक, कामगार, सरकारी सहयोग और समर्थन, मोटी धनराशि और वक्त भी चाहिए। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ जैसी विश्व प्रसिद्ध जगह पर सड़की मंडी से मटर खरीदते हुए मैंने विक्रेता को पॉलिथीन बैग में न देकर कागज का लिफाफा देने को कहा तो उसने कहा- ‘सर जी पहले पॉलिथीन के बैग का उत्पादन रुकना चाहिए’। मेरे पास बड़ा बैग था, लेकिन उसमें सारे फल वास्तविक रूप में उपलब्ध होना उचित न होता या फिर मैं कई छोटे थैले लेकर जाता। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि चालान किए जा रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रशासनिक पहुंच है, उन्हें अभी भी ज्यादा परेशानी नहीं है। जो प्लास्टिक उत्पाद देश भर में बन चुके हैं, उन्हें चाहे प्रयोग न करें, लेकिन भविष्य में प्लास्टिक के विकल्प का होना योजना स्तर पर या बातों और सरकारी घोषणाओं में नहीं, बल्कि जूट या कपड़े के थैले की तरह वास्तविक रूप में उपलब्ध होना लाजिमी है। प्लास्टिक के उत्पादन को कम करते हुए आमजन के लिए इसका उपयुक्त विकल्प तैयार कर उसका प्रयोग बढ़ाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्य-संस्कृति की शानदार परंपरा के अनुसार विकल्पहीनता के आसन पर बैठ कर अविलंब परिवर्तन की अपील करना हमारी श्रेष्ठ आदतों में शुमार है, जिसका शोधन और संशोधन अब बदलते वक्त की मांग है।

और खेतीबाड़ी का धंधा लाभदायक नहीं रहने की वजह से वह पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है।

● ***राजीव शर्मा, कोटकपूर, पंजाब***

**धुवीकरण से दूर**

सन 1986 से निरंतर चर्चा में बने रहने वाले राम जन्मभूमि-बावरी मस्जिद विवाद की सुनवाई आखिरक उच्चतम न्यायालय ने पूरी कर दी है। सभी पक्षों की लिखित दलीलें मिलने के बाद पांच जजों का संविधान पीठ फैसला सुनाएगा। जिसने इस मामले को फौरी निगाहों से ही देखा होगा वह भी जनता होगा कि पंडीबेल्टर 2.77 एकड़ जमीनी को लेकर है। इस मसले को देखकर प्रेमचंद के उपन्यास ‘रंगभूमि’ का पात्र सूरदास याद आ जाता है जो अपनी जमीन के टुकड़े को नहीं बेचना चाहता क्योंकि वह उसकी जुड़क संपत्ति है और उससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी ही स्थिति अयोध्या विवाद की है; एक जमीन का टुकड़ा है और देर सारी भावनाएं हैं!

लेकिन यह जमीन का टुकड़ा और भावनाएं एक और जगह भी होती हैं वे हैं हमारे गांव। हमारे गांवों में अक्सर देखा जाता था कि एक समाज के लोग जमीन दान कर दूसरे समाज के लोगों को गांव में लेकर आते थे भले ही यह प्रक्रिया वर्ण-व्यवस्था से प्रेरित थी लेकिन यह सामाजिक सद्भाव और विविधता को बढ़ाने वाली थी। यही हमारे भारत का स्वभाव रहा है जबकि अयोध्या मामला अलग ही दिखाई देता है। यह न केवल भारत के ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आदर्श के विपरीत है बल्कि देश की समस्या को भी खतरा है। इसके अलावा यह मामला भावनाओं से कम, राजनीतिक धुवीकरण से जुड़ा ज्यादा प्रतीत होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो हो इसे अवैधानीय धुवीकरण से बचना होगा और हमारी ग्रामीण संस्कृति को लाज रखनी होगी।

- सचिन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय***



धर्म भी अब अपने देश में बड़ा उद्योग है। उद्योगपतियों को घन-दोलत का तो फिर भी पता चल जाता है पर साधू-संत-महात्मा-धर्माचार्य कितने मालदार हैं, इसका पुख्ता आकलन कोई नहीं कर पाता। दरअसल धर्माचार्यों और मठाधीशों की घन संपदा उनके ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसायटी के स्वामित्व में होने से कभी सामने नहीं आ पाती उनकी माली हैसियत। अब अपने सतपाल महाराज को ही लें। कहने को तो धर्माचार्य हैं। पर गृहस्थी हैं सो संत-महात्मा नहीं हो सकते। सियासत में तो गढ़वाल में पकड़ है ही, देश भर में अनुयायियों की तादाद भी करोड़ों में है। कहां नहीं हैं उनकी संपत्तियां। आजकल उनके बेटे की शादी के चर्चे हैं। जैसे कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं और ओली में पिछले दिनों सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं की शादी शादी की चर्चा हुई थी। महाराज के बेटे सुयश का वरण रीवा की राजकुमारी मोहिनी ने किया है। टीवी धारावाहिकों की अभिनेत्री हैं मोहिनी। विवाह समारोह का पंडाल किसी महल से कम नहीं था। शादी शादी थी तो एक लाख मेहमान तो आते ही कारिदों ने इतने जमघट के बावजूद कमाल का यातायात बंदोबस्त किया। कितने राजनेता और शाही घरानों के नुमाइंदे पहुंचे। कई बड़े कांग्रेसी भी थे पर हरीश रावत नहीं दिखे। सतपाल महाराज भी रावत ही ठहरे। सो, दोनों के बीच एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति है। पहले महाराज भी कांग्रेसी थे। हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में पाला बदला। इस शाही शादी के निहितार्थ तलाशने से भी उनके विरोधी चूक नहीं रहे। दबी जुबान से ही सही पर कहने से चूक नहीं रहे कि बेटे के शादी समारोह के बहाने सतपाल महाराज ने अपनी पैट और रसूख का प्रदर्शन कर दिखाया।

शाही शादी

हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां विपक्ष जनता से दूर और अंदरूनी कलह में मशगूल है वहां विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे गायब हैं और केंद्र के हालिया लिए राजनीतिक फैसले ही राष्ट्रीय मुद्दा बन वोट मांगने का आधार बन रहे हैं। कांग्रेस के नेता अशोक तंवर ऐन चुनावी समय में नवनिर्मित जननायक जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई आश्चर्य नहीं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष को सजा देने की मांग करता है। भारत की राजनीति का यह अहम अध्याय है कि



बेसाख विपक्ष के कारण सत्ता पक्ष ही एजंडा बना और दोषी तय कर रहा। वहीं दिल्ली, जहां चुनाव अभी दूर है और भाजपा विपक्ष में है, स्थानीय मुद्दों पर पुरजोर बहस जारी है। वहां विपक्ष चुनाव जीतने की कोशिश में जुटा है। भाजपा दावा कर रही है कि वह सरकार बनाने और बाकी दल हैसियत बचाने के लिए मैदान में हैं। विपक्षी दलों की राजनीतिक काहिली ने जिस तरह लोकतंत्र को एकतरफा बना दिया है उसकी पड़ताल करना बेबाक बोल।

# पक्ष ही विपक्ष

मुकेश भारद्वाज

कथित बाबाओं के समर्थकों का शुरू किया हुआ फसाद हो या जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फैली अराजकता। बाबाओं के डेरों से श्रद्धालुओं के रूप में निकलते दंगाई और मारे गए लोगों का आंकड़ा। कारों की खरीद-बिक्री में सुरती और कई तरह के कारखानों में मंदी के बाद हरियाणा के एनसीआर से जुड़े कई शहरों में बेरोजगारी का आलम। हरियाणा में इन स्थानीय मुद्दों की कहीं गूंज नहीं है। नवनिर्मित जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जब इन पर बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने अनुच्छेद 370 और कश्मीर का मसला उछाल दिया जाता है।

वहीं महाराष्ट्र में वीर सावरकर से लेकर तीन तलाक और 370 जैसे मजबूत राजनीतिक फैसले के मुद्दे छाप हुए हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मुद्दे हावी हैं। आखिर स्थानीय मुद्दों की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही?

स्थानीय मुद्दे जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, सूखा-बाढ़, कानून व प्रशासन आम जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। किसानों का सवाल, आदिवासियों का सवाल और इन सबसे जुड़ा रोजी-रोटी का सवाल। लोकतंत्र में नाकामियों को उभार कर उस पर सवाल-जवाब करना विपक्ष का काम होता है। सत्ता पक्ष यह नहीं कहगा कि देखो, हमारे शासन में एक कथित बाबा के समर्थकों के फैलाए दंगे में इतने लोग मारे गए तो आरक्षण जैसे मुद्दे पर एक खास वर्ग ने पूरे राज्य की मशीनरी को बंधक बना डाला था, और हमारी सत्ता मुकदमेशक बनी रही। हर सत्ता यह जानती है कि सामूहिक याद की उम्र बहुत छोटी होती है। जनता के सामने सत्ता के खिलाफ उन यादों का पिंटारा खोलने वाला विपक्ष ही जब मैदान से गायब हो तो वह करे भी तो क्या?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन तो किया लेकिन वह 2014 के बाद से अब तक विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं सीख पाई है। 2014 के बाद शुरुआती समय तक तो कांग्रेसी नेतृत्व यही मानकर चलता रहा कि आने वाले चुनावों में जनता उसे महज इसलिए चुन लेगी क्योंकि वह वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। उसने अपनी वापसी के लिए जनता से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसे उस किसान आंदोलन का फायदा मिला जो जनवादी आंदोलनों से जुड़े संगठनों ने शुरू किया था। इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को जो आंतरिक युद्ध लड़ना पड़ा उससे साफ जाहिर है कि पार्टी को जनता के बीच की पैट का ख्याल ही नहीं है।

हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों राज्यों में सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे कि वे विपक्ष को किसी गिनती में ही नहीं रख रहे। महाराष्ट्र में भाजपा को किसी की फिक्र है तो भी वह शिवसेना जैसे सहयोगी दलों की। विपक्ष के नेता तो अपने इस्तीफों और दूसरी पार्टी में शामिल होने



फोटो : अरुण चोपड़ा

के कारण सुखियां बन रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रेस सम्मेलन करते हैं तो यह बताने के लिए कि उन्होंने तो बस चार उम्मीदवार के नाम दिए थे और पार्टी ने उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया तो फिर क्या फायदा ऐसी पार्टी में रहने का।

हरियाणा में लोकसभा चुनावों में जिस अशोक तंवर ने कांग्रेस के लिए लिए सबसे ज्यादा मेहनत की एन विधानसभा चुनावों के दौरान वो जननायक जनता पार्टी की प्रकाश वार्ता में दुष्यंत चौटाला के साथ हताश और निराश बैठे थे। जिन तंवर को भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर होना था वो दिल्ली में अपनी ही पार्टी के मुख्यालय के बाहर समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा से लेकर केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के कदावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इन दिनों प्रभाव के स्तर पर पदों के पीछे ही दिख रहे हैं। अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद परिवार से बाहर दूसरा अध्यक्ष नहीं मिलना भी पार्टी की सीमा बता रहा।

केंद्र सरकार ने अपने खतरे उठा कर मजबूत राजनीतिक फैसले किए और अब वह राज्यों में इसका फायदा उठा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता इन मजबूत फैसलों पर इतने कमजोर हैं कि अनुच्छेद 370 पर हुड्डा का रुख अलग तो गुलाम नबी आजाद का रुख अलग रहता है। यही हाल जीएसटी से लेकर तीन तलाक तक के फैसलों पर रहा। कांग्रेस नेताओं के सुरु अलग-अलग रहे। कांग्रेस जब इस पर रुख ही नहीं तय कर पा रही है तो मुद्दा कैसे बना पाएगी।

हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है

लेकिन कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में एक अदद प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं दे सका है। इसके पहले भी बुजुर्ग शीला दीक्षित को प्रदेश की कमान सौंपी गई। लेकिन कांग्रेसी नेता ही कहने लगे कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब शीला दीक्षित के बेटे पत्र लिख कर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में कीर्ति आजाद का नाम भी सामने आया है। आजाद को पूर्वांचल के चोटों की खातिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के बरकस लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली की जनता के बीच तिवारी और आजाद के जमीनी आधार में जमीन और आसमान का अंतर है। तिवारी पिछले कई सालों से दिल्ली के लोगों के बीच अथक मेहनत कर रहे हैं। कीर्ति आजाद का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में वरिष्ठता की जंग भी छिड़ गई है। देखते हैं कि कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह से निपट कर विधानसभा चुनाव में कब कूदती है।

हरियाणा और महाराष्ट्र के उलट दिल्ली में स्थानीय मुद्दे हावी हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मुफ्त बिजली-पानी और मेट्रो-बसों में सफर के खिलाफ आंदड़े जुटाए जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। दिल्ली में जबकि चुनाव थोड़े दूर हैं स्थानीय मुद्दों पर चर्चासाल इसलिए मचा है क्योंकि यहाँ विपक्ष में भाजपा है। भाजपा अभी केंद्र से लेकर ज्यादातर जगहों की सत्ता में है, इसलिए उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में जीत की भूख है। जब विपक्ष में जीत की भूख होगी तभी वह सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर होगा। अन्य राज्यों में विपक्ष जीत की उम्मीद खो चुका है। ऐसे माहौल में सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने और अन्य दल अपनी हैसियत बचाने के लिए मैदान में हैं।

जनता के मुद्दों को उठाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना होता है। कांग्रेस के संगठन का ढांचा ढह चुका है और वह चंद नेताओं और उनके समर्थकों की पार्टी बनकर रह गई है। विकल्प का चेहरा बनने की राह में भी वह बेसाख हो चुकी है।

कांग्रेस और अन्य दलों के जनता से दूर होने का नतीजा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्ष की भूमिका भी पक्ष ही निभा रहा है। एजंडा भी वही तय कर रहा है और दोषी भी वही तय कर रहा है। विपक्ष की काहिली का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि इन चुनावों में सत्ता पक्ष के द्वारा उसे ही सजा देने की बात हो रही है। स्थानीय असफलता, विधायकों और सांसदों की नाकामी को सत्ता पक्ष पीछे धकेलने का ही काम करेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने बीच वृहत्तर एकता ही नहीं बना पा रहे तो वे जनता के बीच कैसे स्वीकृत होंगे? देखा है, विपक्ष इस मरणासन अवस्था में कब तक रहता है।

इस विशेष पन्ने पर आपके डेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुश्किल नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएँ। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

## आपके पत्र

### चीन की पिघलती दीवारें

‘शीर्ष पर संवाद’ का चित्रण दोनों देश के मध्य सकारात्मक भविष्य की एक ऐसी पटकथा की परिकल्पना है जो भावुकता की भित्ति पर भय प्रसाद सा दिखता है। लेकिन जब अतीत के पन्नों को हम पलटते हैं तो उसमें अविश्वास, धूर्तता, वैमनस्य की अंतहीन घटित घटनाएं हमें चिंतित भी करती हैं और शत्रु के मित्र से निपटने के लिए सावधानी का पाठ भी पढ़ाती है। मोदी सरकार ने 2014 से ही एक अथक प्रयास कर चीन की मानसिकता में यह कूट-कूट कर भाव भरने में सफलता पाई है कि 1962 के जटिल पड़ाव से आज भारत पूरी तरह उबरकर संसार के केंद्र में अपनी आभा बिखरने में योग्य सिद्ध हुआ है। इतिहास की घटनाओं में दम है कि कभी पंचशील के पंचामृत से तृप्त हिंदी चीनी भाई-भाई के कृत्रिम शंखनाद को चीन ने प्रतिकूलता के भंवर में ला खड़ा किया था और 1962 के युद्ध की विभीषिका से हम आक्रांत हुए थे। केंद्र की नीतियों का असर है कि चीन की दादागीरी अब आर्थिक रूप से विवर्जन की ओर उन्मुख है और बुद्ध के इस देश को अब युद्ध की जगह सिर्फ संवाद से निपटने की वैश्विक मांग है। हां, हमारे वैदेशिक रणनीतिकारों को सावधान रहना होगा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का समर्थन अब चीन को प्राप्त न हो लेकिन आजाद कश्मीर में चीन का आर्थिक गलियारा निर्माण भारतीय हितों के विरुद्ध तो है ही, जिसे अति सूक्ष्म कूटनीति से निपटना होगा। हांगकांग और तिब्बत के आंतरिक कलह और तिब्बत ने चीन की मजबूत दीवारों में कुछ दरार तो डाली है, लेकिन अरुणाचल पर इसकी कुटिल निगाहें भी हमें सावधानी हेतु प्रेरित करती हैं। हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि जो उत्पादकीय सामग्री हम चीन से आयात करते हैं-उसका स्वदेश में निर्माण क्यों नहीं कर

सकते? इस संदेश को यदि चीन समझ ले तो उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का आंशिक पलायन हो सकेगा।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

### महाबलीपुरम में महामिलन

शीर्ष संवादों में पाकिस्तान आक्रमणकारियों की भाषा इस्तेमाल कर अपनी छवि विकृत कर चुका है। जबकि युद्ध और आतंक के बोझ से दबी दुनिया देर ही सही पंचशील के भारतीय सिद्धांत पर आगे बढ़ने को तैयार दिखती है। लिहाजा महाबलीपुरम में महामिलन के नतीजों पर नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा।

-एम्के मिश्रा, मां आनंदमयनीनगर, रातू।

### आर्थिक गुलामी न स्वीकारे भारत

भारत के गुलाम होने का आधार था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। अगर महात्मा गांधी ने भारतीयों को स्वदेशी के प्रति जागरूक नहीं किया होता तो आज शायद भारत आजाद भी नहीं हुआ होता। आज एक बार फिर से भारत विदेशी सामान के मोह में फंसाता जा रहा है, खास तौर पर चीन के। इस कारण भारत अपने नापाक पड़ोसी की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ही रहा, साथ ही अपने देश के घरेलू उद्योग-धंधों की बर्बादी का कारण भी बन रहा। भारत को व्यापार के मामले में दूसरे देशों के साथ इस तरह समझौते करने चाहिए जिससे देश में रोजगार बढ़े।

-राजेश कुमार चौहान, जलंधर।

### नेपाल पर भी रहे नजर

भारत में अपने दो दिवसीय दौरे को खत्म कर चीनी राष्ट्रपति नेपाल गए। उनका नेपाल का यह दौरा भारत के लिए भी अहम है। वर्तमान नेपाल सरकार कहीं न कहीं भारत के पक्ष में नहीं है। उस पर से भारत-नेपाल के आपसी विवाद जिसमें व्यापार, सीमा विवाद शामिल हैं उसे भी सुलझाया जाना बाकी है। इसके बाद अब चीन का नेपाल के करीब आना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। चीन ने अपने इस दौरे में दो साल में नेपाल को 35 अरब रुपए देने का वादा किया है। साथ ही 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसपर भारत को अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नया मसला खड़ा न हो।

-ज्योति सिंह, कानपुर।

### शीर्ष पर संवाद

प्राचीन काल के यूनानी राज्यों एथेंस और स्पार्टा के समय से ही यह बात सिद्ध हो चुकी है कि युद्ध पिपासु देश नष्ट हो जाते हैं। शांति और साहचर्य से रहने वाले देश सांस्कृतिक, साहित्यिक और लालित्य कलाओं में खुद को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा देते हैं। आज इसके ज्वलंत उदाहरण एक ही उपमहाद्वीप के दो टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं। इसलिए अपने इतिहास की कड़वी स्मृतियों को इन दोनों महाशक्तिशाली देशों भारत और चीन को मामलापुरम में कूड़ेदान में सदा के लिए दफन कर देना चाहिए और भविष्य में किसी को भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपसी संबंध फिर से असहज और अविश्वास भरा बन जाए।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

## राजपाट

### करामाती करतार

हरियाणा की धरती लालों यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के लिए भी मशहूर हुई। पर इसी धरती की शान में मोकापरस्ती के लिए भड़ाना बंधुओं ने भी कम गुल नहीं खिलाए। अवतार सिंह भड़ाना और करतार सिंह भड़ाना दोनों गुर्जर बंधुओं ने साबित कर दिखाया कि जब भारी हो और जात का समर्थन भी हो तो हर दल गले लगाएगा। शुक्रवार को करतार सिंह भड़ाना का फिर हृदय परिवर्तन हुआ। भाजपा की नीतियों ने ऐसा मोह लिया कि वे बसपा का चोगा उतार भाजपा में शामिल हो गए। अंतरराज्यीय असर वाले हैं तभी तो हर दल पलक पांवड़े बिछाता रहा है। भाई अवतार सिंह भड़ाना को तो देवीलाल ने 1987 में विधानसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद अपनी सरकार में छह महीने के लिए मंत्री बना दिया था। पर करतार की किस्मत चमकी 1996 में जब बंसीलाल ने अपनी अलग हरियाणा विकास पार्टी बनाई। वे पानीपत की समालखा सीट से हविपा के विधायक चुन लिए गए। उनकी 'प्रतिभा' से प्रभावित हो बंसीलाल ने उन्हें मंत्री भी बना दिया। पर वर्ष 2000 में उन्होंने ही हविपा सरकार के पतन की प्रस्तावना लिखी। इस बार मध्यावधि चुनाव हुआ तो वे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलोद में चले गए। फिर विधायक बन गए। इसके बाद हरियाणा में दाल गलनी बंद हो गई तो 2012 में यूपी पहुंच गए। अजित सिंह के रालोद से टिकट ले खतौली से विधायक बन गए। पर अगली बार इसी पार्टी से बागपत से हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा चुनाव हुए तो इस साल रालोद छोड़ बसपा में चले गए और मध्यप्रदेश की मुरैना सीट से चुनाव लड़ भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर से हार गए। सूक्ति रसूख की सियासत से संजीवनी लेते हैं सो शुक्रवार को फिर हृदय परिवर्तन हुआ और भाजपा में शामिल हो गए।

### हाल-बेहाल

उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ है। इतना रसातल में तो 1984 की कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की आधी के बाद भी नहीं गया था विपक्ष। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में अविभाजित उत्तर प्रदेश की 85 में से 83 सीटों पर कांग्रेस भारी अंतर से विजयी हुई थी। चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे धुरंधर भी ढेर हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो विपक्ष ने अपनी अच्छी उपस्थिति दिखा दी थी। पर 2014 के बाद से यूपी में भाजपा के प्रभुत्व ने ऐसा रंग जमाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के आगे ही वजूद बचाने का संकट है। विधानसभा में 2017 में सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव का कांग्रेस से हाथ मिलाना भी कारगर नहीं हुआ। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया तो घबराहट भाजपा को भी हुई। इस गठबंधन से बसपा तो शून्य से दस तक पहुंच गई पर सपा पांच की पांच पर ही अटकती रह गई। मोदी की आधी का तो असर था ही, सपा के यादव कुनबे की आपसी कलह ने भी कोढ़ में खाज का काम कर दिया। खुद को महागठबंधन में नहीं लिए जाने से कांग्रेस की मिट्टी तो पलीद हुई ही, सपा-बसपा को भी नुकसान ही हुआ। कांग्रेस की तो लाज भी नहीं बच पाई। गढ़ अमटी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह हरा दिया। रायबरेली में भी सोनिया गांधी की जीत का फासला काफी नीचे आ गया। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में हुए विधानसभा की एक और लोकसभा की तीन सीटों के उपचुनाव में विपक्ष ने एकता का प्रदर्शन कर भाजपा को मात दी थी। इस 21 अक्टूबर को सूबे में विधानसभा की 11 सीटों का उपचुनाव है। भाजपाई सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि 2017 में ये सीटें भाजपा ने ही जीती थीं। तो भी विपक्ष एकजुट रहता तो भाजपा से कुछ सीटें जरूर झटक सकता था। एकता को पलीता सबसे पहले मायावती ने लगाया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के फौरन बाद सपा और अखिलेश यादव पर तोहमत लगा उनसे नाता तोड़ लिया। अखिलेश ने फिर भी मर्यादा नहीं तोड़ी। मायावती के बारे में कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की। मायावती भूल रही हैं कि जब यूपी में ही उनका कोई आधार नहीं बचेगा और तमाम नेता एक-एक कर भाजपा में चले जाएंगे तो कैसे वे सत्ता का सपना पूरा कर पाएंगी। सभी 11 सीटों पर सपा, बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। भाजपा को बिखरा विपक्ष हरा तो क्या पाएगा, अपनी जमानत भी सब जगह बचा ली तो गनीमत होगी।

### सब्र की इतिहा

राजस्थान की गहलोल सरकार अब समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों के दबाव में है। विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव के नतीजों से भी कांग्रेस सरकार के मनोबल का पता चलेगा। निर्दलीय तो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बेचैन हैं ही, बसपा से कांग्रेस में विलीन हुए आधा दर्जन विधायकों को भी सत्ता की मलाई की दरकार है। दो सी सदस्यों वाली विधानसभा में अब गहलोल को 105 विधायकों का समर्थन है। उपचुनाव की दो सीटों में से एक भी हाथ लग जाए तो सोने में सुहागा होगा। सरकार बने एक साल होने वाला है। लिहाजा निर्दलियों और पूर्व बसपाइयों के सब्र का बांध टूटने लगा है। सबको मंत्री पद नहीं दे सकते तो निगम या दूसरे समकक्ष ओहदे तो देने ही चाहिए। ज्यादातर निर्दलीय कांग्रेसी अतीत वाले ठहरे। गहलोल की दुविधा अपने पार्टी विधायकों का समायोजन भी है। वे इस तरह तितरफा दबाव में होने के कारण मंत्री मंडल विस्तार की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। निर्दलियों की दलील है कि जब रालोद के इकलौते विधायक सुभाष गर्ग को मंत्री बनाया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। फिलहाल तो अफसरों के तबादलों में हस्तक्षेप की छूट और कुछ दूसरे कामों की सिफारिश के अवसर देकर निर्दलियों की मिजाजपुर्षा में सफल रहे हैं। पर इस स्थिति को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे गहलोल। इस मिजाजपुर्षा को देख कांग्रेसी विधायकों को जलन और मलाल दोनों हो रहे हैं कि उनकी कोई पूछ नहीं। उनसे तो निर्दलीय ही अच्छे।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)



# शाह ने राहुल से पूछा, आदिवासियों के लिए आपके परिवार ने क्या किया

गढ़चिरौली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि उनकी चार पीढ़ियों ने 70 साल के शासन के दौरान जनजातीय समुदाय के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को अगले पांच साल में नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। पूर्वी महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित गढ़चिरौली के अहेरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस नीत सरकारों ने वोट-बैंक की राजनीति के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया। अंततः मोदी सरकार ने इस विवादास्पद प्रावधान को समाप्त किया जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था।

शाह ने आदिवासी बहुल जिले में आयोजित रैली में राहुल गांधी के लिए सवाल किया, ‘आपकी चार पीढ़ियों ने 70 साल तक

## सुन्नी वक्फ बोर्ड के मामला वापस लेने की खबरों पर मुसलिम पक्षकारों ने जताई हैरानी

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

अयोध्या भूमि विवाद में मुसलिम पक्षकारों ने बयान जारी कर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा मामला वापस लेने संबंधी खबरों पर शुक्रवार को हैरानी जताई। अयोध्या भूमि विवाद में अहम मुसलिम वादी एम सिद्दीक के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर सभी मुसलिम पक्षों ने समझौते को खारिज कर दिया है क्योंकि विवाद के मुख्य हिंदू पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया और इसके तथाकथित समाधान का हिस्सा नहीं थे।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर मुसलिम पक्षकारों ने स्पष्टीकरण बयान जारी कर कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता समिति के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को सौहार्दपूर्वक सुलझाने के लिए

देश पर शासन किया, आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? आपने मोदीजी को केवल पांच साल दिए और हमने इस दौरान समुदाय के लिए बहुत काम किया।’ भाजपा अध्यक्ष ने गांधी और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधते हुए उनसे जिले में तत् महााराष्ट्र में किए गए उनके कामकाज का हिसाब देने को कहा, जहां 1999 से 2014 तक 15 साल तक कांग्रेस–राकांपा सरकार रही।

उन्होंने 78 वर्षीय पवार को इस मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोचां का अध्यक्ष से बहस करने की चुनौती दी कि किसकी सरकार ने क्या काम किया है। शाह ने कहा, ‘हमारे पांच साल का काम आपके 50 साल के शासन से बेहतर साबित होगा। हम बहस के लिए तैयार हैं।’ उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस–राकांपा की सरकारों ने महाराष्ट्र को 13वें वित्त आयोग के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए दिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 4.38 लाख करोड़ रुपए दिए।

## तथाकथित समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। बयान में कहा गया, ‘हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शाहिद रिजवी के हवाले से मीडिया में आ रही इन खबरों से हैरान हैं’

उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड बाबरी मस्जिद स्थल पर अपना दावा वापस लेने का इच्छुक है।’ इसमें कहा गया है, ‘हम यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम, अपीलकर्ता, प्रेस को लीक किए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, हम न ही मध्यस्थता की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं और न ही दावे की वापसी को समझौता बनाने वाले तरीके को स्वीकार करते हैं।’ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर 40 दिन सुनवाई करने के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

## दिल्ली की आबोहवा हुई और खराब

हवा की गुणवत्ता के विगड़ने का कारण मौसम की स्थिति में धीरे-धीरे बदलाव होने से भी है। तापमान कम होने से भी प्रदूषक निचले स्तर पर बने हुए हैं। दिल्ली के वातावरण में महीन धूलकणों की मात्रा (पीएम 2.5) में पराली जलाने की भागीदारी 10 फीसद हो गई है। सफर के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को यह 18 फीसद तक बढ़ने का अनुमान है। सफर की रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा, पंजाब,पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार पराली जलने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

पंजाब और आसपास के राज्यों में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पराली जलाने की अधिकतम घटनाएं होती हैं। यह दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद, वित्तीय

गढ़चिरौली जिले के नक्सल प्रभावित होने के संदर्भ में शाह ने कहा कि पहले प्रचार किया जाता था कि नक्सलवाद की मुख्य वजह विकास नहीं होना है। हालांकि हकीकत में माओवादी विकास के विरोधी हैं। शाह ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में बिजली, अच्छी सड़कें, रेल सेवाएं और अन्य सुविधाएं पहुंचाना चाहती है, लेकिन नक्सली यह नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा, ‘किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदीजी ने पिछले पांच साल में नक्सलवाद पर लगाम कसी है। हम इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि यहां के नौजवान बाकी दुनिया के युवाओं से स्पर्धा कर सकेंगे।’ भाजपा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र और कश्मीर की बात एक साथ करने का विरोध किये जाने पर कांग्रेस–राकांपा निशाना साधा और कहा, ‘राहुल बाबा इतिहास पढ़ो। यह शिवाजी महाराज और सावकर की सरकार है। इस भूमि के संपूत कभी देश की हिफाजत से पीछे नहीं हटे।’

## मित्र देशों के साथ सैन्य साझेदारी पर जोर : सेना प्रमुख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि भारत पड़ोस के साथ-साथ ‘वृहद क्षेत्र’ में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सेना ‘किसी भी तरह के उभरते खतरों से निपटने’ के लिए अपने मित्रों के साथ साझेदारी करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हम धीरे-धीरे एक मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम सिर्फ अपने सुरक्षाबलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे, बल्कि धीरे-धीरे निर्यातों-मुख्खी रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में हमारा रक्षा निर्यात सालाना 11,000 करोड़ रुपए है, जो 2024 तक बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।’

## पहलू खान मामले में हाई कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार

जयपुर, 18 अक्टूबर (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने पहलू खान की २२हत्या मामले में अलवर की एक अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल, 2017 को कुछ लोगों ने गो तस्करी के संदेह में पहलू खान और उनके बेटे की बुरी तरह पिटाई की थी। पहलू खान की तीन अप्रैल के अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में अपील सोमवार को दायर की गई।

अलवर की अदालत ने मामले में शामिल सभी छह आरोपियों विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए 14 अगस्त, 2019 को बरी कर दिया था। अगस्त में चित्तौी अदालत के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जांच में जुटियों और अनियमितताओं की पहचान करने और व्यक्तिगत अधिकारियों पर जांच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया था।

## रक्षा अताशे के चौथे सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा, ‘हम केवल आकार के आधार पर ही नहीं, बल्कि हमारे वृहद लड़ाकू अनुभव,

हमारी पेशेवर दक्षता और अन्य गुणों के कारण दुनिया के अग्रणी सशस्त्र बलों में से एक हैं।’ इस सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में समुद्री डकैतों जैसे समुद्री खतरों का हवाला दिया है, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है। उन्होंने समुद्री सहयोग बढ़ाने और विश्व में ‘सामूहिक सैन्य दक्षता’ का लाभ उठाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, ‘हमें एक दूसरे से सीखना होगा।’

इस सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा, ‘हम सिर्फ अपने सुरक्षाबलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे, बल्कि धीरे-धीरे एक रक्षा निर्यात उद्योग बन रहे हैं। मौजूदा समय में

## भूख से लड़ने के लिए सामुदायिक भोजनालय के पक्ष में न्यायालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामुदायिक भोजनालय बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि भूख की समस्या से निपटने के लिए देश में इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति एनबी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया और साझी रसोई बनाने के प्रस्ताव पर

## ‘जेल में 43 दिन में पांच किलो वजन कम हुआ’

पेज 1 का बाकी
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ को चिदंबरम के वकील कपिल सिब्वल ने बताया कि जेल में 43 दिन रहने के दौरान वे दो बार क्रम से पांच और सात दिन के लिए बीमार पड़ गए थे और उन्हें एंटीबायोटिक दिए गए।’ उन्होंने अदालत को बताया, ‘उनका वजन 73.5 किलोग्राम से कम होकर 68.5 किलोग्राम हो गया है।’

## प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे समुद्री खतरों की ‘अंतरराष्ट्रीय’ प्रकृति है और उन्होंने एक दूसरे की सर्वोत्तम नौसेना कार्यप्रणाली को जानने के लिए ‘सामूहिक सैन्य क्षमता’ को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के साथ सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नौसेना प्रमुख ने कहा, ‘यहां कई सामुद्रिक जोखिम और साझा चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए समुद्री डकैती, जहां हमला एक देश में होता है और जहाज में दंडा माल दूसरे देश में पहुंच जाता है। फिर नशीले पदार्थों की तस्करी है, जिसे हम नाकों-आतंकवाद कहते हैं, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने का कारोबार भी है। इन सभी का एक अंतरराष्ट्रीय या अंतरक्षेत्रीय चरित्र है।’

प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे समुद्री खतरों की ‘अंतरराष्ट्रीय’ प्रकृति है और उन्होंने एक दूसरे की सर्वोत्तम नौसेना कार्यप्रणाली को जानने के लिए ‘सामूहिक सैन्य क्षमता’ को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के साथ सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नौसेना प्रमुख ने कहा, ‘यहां कई सामुद्रिक जोखिम और साझा चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए समुद्री डकैती, जहां हमला एक देश में होता है और जहाज में दंडा माल दूसरे देश में पहुंच जाता है। फिर नशीले पदार्थों की तस्करी है, जिसे हम नाकों-आतंकवाद कहते हैं, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने का कारोबार भी है। इन सभी का एक अंतरराष्ट्रीय या अंतरक्षेत्रीय चरित्र है।’

जनरल रावत ने कहा कि हर देश शांति, स्थिरता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों या मुझे कहना चाहिए मजबूत सशस्त्र बलों को बनाए रखता है। उन्होंने कहा, ‘शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को जब भी बुलाया जाए, वे तब अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हों, इसके लिए आपको एक बहुत दक्ष एवं सशक्त मानवबल, सैनिकों, नौसैन्यकर्मियों और वायुसेनाकर्मियों की जरूरत है। अच्छा प्रशिक्षण और अच्छी गुणवत्ता के हथियार एवं उपकरण जवानों को सशक्त करते हैं।’ इस सम्मेलन में नौसेना

## 570 हटाने से कांग्रेस के पेट में दर्द : मोदी

दिवक्त होती है और अगर कोई बालाकोट का नाम लेता है तो उनका दर्द बढ़ जाता है।’ मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के बारे में कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए वे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो पाकिस्तान को पसंद आते हैं। उन्हें कुछ ऐसा कहना चाहिए जिसे भारत के लोग पसंद करें।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी के बारे में अच्छा बुरा कह सकते हैं, लेकिन काम से कम मां भारती का सम्मान करना चाहिए। हद पार नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो।’ मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का विरोध किया था, ‘अब यह समूह हरियाणा का प्रभार संभालने आगे आ रहा है।’ सोनीपत जिले में आने वाले गोहाना को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना

जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुड्डा सोनीपत संसदीय सीट से और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक संसदीय सीट से हार गए थे। इस पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा ‘आपने लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं का अंहकार तोड़ दिया।’

परोक्ष रूप से हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘जो लोग सोच रहे कि सोनीपत, रोहतक और जींद उनका गढ़ है, तो लोगों ने (लोकसभा चुनावों में) अपना फैसला सुना दिया था।’ भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हरियाणा में तीन साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुषी हिंसा का परोक्ष रूप से हवाला देने हुए मोदी ने कहा कि भाईचारा खत्म करने वालों को सबक सिखा दिया गया। हिसार में एक अन्य रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में पहले से ही हार मान ली है।

## ‘यात्रियों में देशभक्ति’ पैदा करने के लिए स्टेशनों पर फहरेंगे राष्ट्रीय ध्वज

भुवनेश्वर, 18 अक्टूबर (भाषा)।

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने ‘यात्रियों में देशभक्ति पैदा करने’ के लिए जून के 26 रेलवे स्टेशनों पर 100 फुट ऊंचे स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ लगाने का फैसला किया है। रेलवे ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यात्रियों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करने के रेल मंत्रालय के निर्देश के तहत रेल मुख्यालयों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय लिया गया है। भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज पहले ही लगाए जा चुके हैं।

मापदंडों में से 20 में उनके देश का प्रदर्शन सकारात्मक रहा है। एफएटीएफ ने जून 2018 ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए दी गई 27 सूत्रीय कार्ययोजना में इस्लामाबाद सिर्फ पांच पर ही काम कर पाया। भारत में सिलसिलेवार आतंकवादी हमलों के लिए ये दोनों आतंकी संगठन जिम्मेदार रहे हैं।

बैठक में यह आमराय रही कि इस्लामाबाद को दी गई 15 महीने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अचानक मिठाई के साथ ‘काली सूची’ में डाले जाने के जोखिम का सामना करने को कहा गया था।

एफएटीएफ पेरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है। इसका काम आतंकी संगठनों की गैरकानूनी आर्थिक मदद को रोकने के लिए नियम बनाना है और इसके पालन पर अपनी रिपोर्ट देनी है। संस्था का गठन 1989 में किया गया था। एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में कठिनाई आती है। एफएटीएफ ने समीक्षा के दायरे में रहे सभी क्षेत्रधिकारों पर चर्चा की। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और उस पर आमराय भी बनी। अब, फरवरी 2020 में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से काली सूची में डाले जाने की संभावना बढ़ गई है।

रक्षा अताशे के चौथे सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा, ‘हम केवल आकार के आधार पर ही नहीं, बल्कि हमारे वृहद लड़ाकू अनुभव, हमारी पेशेवर दक्षता और अन्य गुणों के कारण दुनिया के अग्रणी सशस्त्र बलों में से एक हैं।’ इस सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में समुद्री डकैतों जैसे समुद्री खतरों का हवाला दिया है, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है। उन्होंने समुद्री सहयोग बढ़ाने और विश्व में ‘सामूहिक सैन्य दक्षता’ का लाभ उठाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, ‘हमें एक दूसरे से सीखना होगा।’

इस सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा, ‘हम सिर्फ अपने सुरक्षाबलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे, बल्कि धीरे-धीरे एक रक्षा निर्यात उद्योग बन रहे हैं। मौजूदा समय में

पेज 1 का बाकी
अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से पार्टी ‘दर्द’ में है। उन्होंने कहा, ‘आपको याद है पांच अगस्त को क्या हुआ? उस दिन वह हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसके बारे में देश ने उम्मीद ही एक तरह से छोड़ दी थी।’ पांच अगस्त को भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू हो गया... 70 साल से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के विकास में हो रही रुकावट को हमने खत्म कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन उसके बाद से कांग्रेस और उसके जैसे दलों को इतना दर्द हो रहा कि उपचार के लिए कोई दवा नहीं है। कांग्रेस के पेट में दर्द कांग्रेस की लाइलाज बीमारी बन गया है।’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ऐसी बीमारी का सामना कर रही है कि जब हम स्वच्छ भारत, लक्षित हमले की बात करते हैं, तो उन्हें

## हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी की हत्या

पेज 1 का बाकी
कुछ साथियों ने इस मामले में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) का हाथ होने की आशंका भी जताई।

बेहद शातिराना अंदाज में मिठाई के डिब्बे में असलहें ले कर आए हत्यारों ने करीब आधे घंटे कमलेश से उनके खुश्रेंदबाग स्थित कार्यालय में बात की और पहले चाकू से उनका गला रेता और फिर उनको गोली मार दी। हमलावरों ने कमलेश पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 से ज्यादा चार किए और उनका गला रेत दिया। कमलेश इस्लामिक स्टेट (आइएस) के भी निशाने पर थे। वर्ष 2017 में गुजरात के अमदाबाद में पकड़े गए आइएस के दो आतंिकियों उवेद मिर्जा और कासिम रिस्टरवाला ने कमलेश को निशाना बनाया

## जुमे के मद्देनजर घाटी में नए सिरे से पाबंदियां

श्रीनगर, 18 अक्टूबर (भाषा)।

शहर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को नए सिरे से पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जुमे की नमाज के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियां सीरा थानाक्षेत्र के तहत आने वाले अंचर इलाके और नौहट्टा थाने के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के आस-पास के इलाकों में लगाई गई है। अधिकारियों ने घाटी के संवेदनशील इलाकों में शुक्रवार को इस आशंका के आधार पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं कि निहित स्वार्थी तत्व विरोध भड़काने के लिए बड़ी मस्जिदों एवं दरगाहों पर जमा भीड़ का फायदा उठा सकते हैं। जामिया मस्जिद में पिछले दो महीने से अब तक जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने

वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की केंद्र सरकार की पांच अगस्त की घोषणा के बाद कश्मीर घाटी में उसी दिन प्रतिबंध लगा दिए गए थे। समय के साथ घाटी में स्थिति सुधरने के साथ ही प्रतिबंधों को कई चरणों में हटाया गया।

इस बीच, शुक्रवार को लगातार 75वें दिन घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बताया कि सुबह में कुछ घंटों के लिए दुकानें खुली लेकिन मुख्य बाजार और अन्य कारोबारी संस्थान बंद रहे। साथ ही शहर में और कश्मीर के अन्य हिस्सों में निजी वाहन बिना किसी बाधा के आते-जाते रहे। हालांकि सार्वजनिक परिवहन के अन्य माध्यम सड़कों से नदारद रहे।

स्कूल एलं कॉलेज भले ही खुले लेकिन बच्चे घर पर ही रहे क्योंकि सुरक्षा के चलते उनके माता-पिता उन्हें घर पर ही रख रहे हैं।

### दरअसल









## मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए निगरानी बढ़ी

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (जनसता)

खाद्य नियामक एफएसएएसआइ ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में त्योहारी मौसम के दौरान मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए खोए और घी जैसे दुग्ध उत्पादों की निगरानी बढ़ा दी है।

Form A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF AL-NAFFES PROTEINS PRIVATE LIMITED	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	AL-NAFFES PROTEINS PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	08.01.1998
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4. Corporate Identity No./ Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15116DL1998PT1001597
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	6, Central Lane, Bengali Market, New Delhi- 110001
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	16.10.2019 (Order recorded on 18.10.2019)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	12.04.2020
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Ram Phal Bhardwaj Regd No: IBB/1/PPA-003/IP-19018/2018-19/123083
9. Address and e-mail of the interim resolution professional as registered with the Board	310/25, Okar Nagar- 6, Tri-Nagar, Delhi- 110035 bhardwajr@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	310/25, Okar Nagar- 6, Tri-Nagar, Delhi- 110035 rpbhardwaj@gmail.com
11. Last date for submission of claims	30.10.2019
12. Classes of creditors, if any, under clause (h) of sub-section (f) of section 21, as claimed by the interim resolution professional	N/A
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N/A
14. (i) Relevant Forms and (ii) Details of authorized representatives	Weblink: <a href="https://ibbi.gov.in/home/downloads">https://ibbi.gov.in/home/downloads</a> Physical Address: N/A.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Al-Naffes Proteins Private Limited on 16.10.2019. The creditors of Al-Naffes Proteins Private Limited, are hereby called upon to submit to their claims with proof on or before 30-10-2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit their claims with proof in cash, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of all the creditors in that class (specifically class) in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Name and Signature of Interim Resolution Professional: RAM PHAL BHARDWAJ

Date and Place : 19.10.2019 and New Delhi

प्रपत्र का सार्वजनिक घोषणा [भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन] मेसर्स यू वी एसएफोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ सूत्रित विनिर्देश

1. कार्पोरेट देनदार का नाम	मेसर्स यू वी एसएफोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निर्माण की तिथि	12 फरवरी, 2014
3. प्राधिकृत निदेशक अधीन कार्पोरेट देनदार निर्माण/पंजीकरण की तिथि	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनियों, दिल्ली
4. कार्पोरेट देनदार को कार्पोरेट पहचान संख्या/सीएनआईएन पहचान संख्या	U1909धरौदर2014पीटीडी26764
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: मेसर्स यू वी एसएफोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जेए-809, 8वीं फ्लोर, डीएफएच टॉवर-ए, जसोलो हिटिडिफ सेंटर, नई दिल्ली-110025
6. कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आदेशन की तिथि	19 सितम्बर, 2019
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14 अप्रैल, 2020 (आदेश प्राप्त अर्थात उक्त ऋण शोध समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180वें दिन)
8. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और: रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : श्री राजेश कुमार गुप्ता IBB/1/PPA-003/IP-19018/2018-2019/12308
9. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	फैक-43, दिलशाद कॉलोनी पूर्वी, दिल्ली-110095. ई-मेल : rgadw21@gmail.com
10. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल का पताकार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	फैक-22, लोअर आउटड्र फ्लोर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 ई-मेल : uvepl.cirp@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्त की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019 से 14वें दिन)
12. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के अन्तर्गत (छा) के तहत अधिनियमित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	निर
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अग्रवचन
14. (क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध	(क) वेब लिंक : <a href="https://www.ibbi.gov.in/home/downloads">https://www.ibbi.gov.in/home/downloads</a> (ख) अधिवचन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रपत्र पीठ ने आदेश दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से मेसर्स यू वी एसएफोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आदेश करने का आदेश दिया है किन्तु अधोस्तरीय को मेसर्स यू वी एसएफोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्तिम समाधानकर्ता के रूप में नियुक्त करने का आदेश 17.10.2019 को प्राप्त हुआ।

1. मेसर्स यू वी एसएफोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्त 2019) के माध्यम से मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को अथवा इससे पूर्व अर्थात् 10 के समक्ष लिखित पत्र पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

2. विन्ती लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ता (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण को प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

श्री राजेश कुमार गुप्ता अन्तिम समाधान प्रोफेशनल मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड IBB/1/PPA-003/IP-19018/2018-2019/12308

प्रपत्र का सार्वजनिक घोषणा [भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन] मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ सूत्रित विनिर्देश

1. कार्पोरेट देनदार का नाम	मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निर्माण की तिथि	24 फरवरी, 2016
3. प्राधिकृत निदेशक अधीन कार्पोरेट देनदार निर्माण/पंजीकरण की तिथि	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनियों, दिल्ली
4. कार्पोरेट देनदार को कार्पोरेट पहचान संख्या/सीएनआईएन पहचान संख्या	U1909धरौदर2016पीटीडी291561
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जेए-809, 8वीं फ्लोर, डीएफएच टॉवर-ए, जसोलो हिटिडिफ सेंटर, नई दिल्ली-110025
6. कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आदेशन की तिथि	19 सितम्बर, 2019 (आदेश प्राप्त अर्थात उक्त ऋण शोध समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180वें दिन)
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14 अप्रैल, 2020 (आदेश प्राप्त अर्थात उक्त ऋण शोध समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180वें दिन)
8. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और: रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : श्री राजेश कुमार गुप्ता IBB/1/PPA-003/IP-19018/2018-2019/12308
9. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	फैक-43, दिलशाद कॉलोनी पूर्वी, दिल्ली-110095. ई-मेल : rgadw21@gmail.com
10. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल का पताकार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	फैक-22, लोअर आउटड्र फ्लोर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 ई-मेल : uvepl.cirp@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्त की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019 से 14वें दिन)
12. अन्तिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के अन्तर्गत (छा) के तहत अधिनियमित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	निर
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अग्रवचन
14. (क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध	(क) वेब लिंक : <a href="https://www.ibbi.gov.in/home/downloads">https://www.ibbi.gov.in/home/downloads</a> (ख) अधिवचन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने आदेश दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आदेश करने का आदेश दिया है किन्तु अधोस्तरीय को मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्तिम समाधानकर्ता के रूप में नियुक्त करने का आदेश 17.10.2019 को प्राप्त हुआ।

1. मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्त करने की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019) से अथवा इससे पूर्व अर्थात् 10 के समक्ष लिखित पत्र पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

2. विन्ती लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ता (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण को प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

श्री राजेश कुमार गुप्ता अन्तिम समाधान प्रोफेशनल मेसर्स इंशाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड IBB/1/PPA-003/IP-19018/2018-2019/12308

दिनांक : 17.10.2019 अन्तिम समाधान प्रोफेशनल स्थान : नई दिल्ली

## शाजापुर (मध्यप्रदेश), 18 अक्टूबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में शुक्रवार को निजी स्कूल के सामने बने करीब 25 फुट गहरे कुएं में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन गिर गई। हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि 18 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है।

शाजापुर जिले के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट उमराव सिंह मरावी ने बताया कि निजी स्कूल 'ए एकेडमी' के

## कुएं में गिरी स्कूली बच्चों से भरी वैन, तीन की मौत

जैसे ही वैन चालक ने वाहन को रिवर्स किया, वैन कुएं में गिरने लगी। वैन के कुएं में गिरने से पहले ही चालक ने वाहन से छलांग लगा दी और वहां से फरार हो गया

छात्रों से खचाखच भरी वैन आज स्कूल के सामने ही बने पानी से भरे कुएं में गिर गई। हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिव्या, हार्दिक और आयुष के रूप में की गई है। आयुष पहली कक्षा का छात्र था जबकि बाकी दोनों एलकेजी में पढ़ते थे। उन्होंने

कहा कि 18 बच्चों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया है जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे छुट्टी होने के बाद वैन (मारुति ओमनी) में बैठकर घर जाने वाले थे। जैसे ही वैन चालक ने वाहन

को रिवर्स किया, वैन कुएं में गिरने लगी। वैन के कुएं में गिरने से पहले ही चालक ने वाहन से छलांग लगा दी और वहां से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि चालक को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने कहा कि वी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुएं में सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ दीवार नहीं बनी थी।

पंजाब नेशनल बैंक		punjab national bank					
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)							
जैसा कि, धितवी परिसरों/वित्तों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तरीय ने मांग सूचना तिथि 23.7.2019 जारी कर ऋणधारक श्री पवन कपूर तथा श्रीमती रीना कपूर को उक्त सूचना की प्रतिलिपि की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.6.2019 को रु. 35,90,396.00 (रुपये पैंतीस लाख रुपये हजार तीन सौ छियासवें मात्र) के साथ 1.7.2019 से आगे के ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक उस पर लागतों एवं खर्च वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के सम्बन्ध में वर्णित तिथि को अधोस्तरीय ने उक्त निष्पादन की नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तरीय ने खर्च नीचे वर्णित संघित का कर्जा कर लिया है।							
व्यवसाय से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संघित का व्यवसाय न करें तथा इन संघितियों को किसी भी तरह का वित्तीय 30.6.2019 को रु. 35,90,396.00 (रुपये पैंतीस लाख रुपये हजार तीन सौ छियासवें मात्र) तथा उस पर आगे के ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन हो।							
ऋणधारक/गारंटर/मॉडरीजर का ध्यान प्रतिभूत परिसरों/वित्तों को धिमोचित करने के लिए उपलब्ध रहने के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत आकृष्ट की जाती है:							
क्रम सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणधारक (सम्पत्ति के स्वामी) का नाम	मिाली सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	संलग्न कच्चा सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	बीएसटी अलकनंदा बुलकानावर एस्टेट, नई दिल्ली-110019	श्री पवन कपूर एवं श्रीमती रीना कपूर	श्री पवन कपूर	एच. नं. 801, इबॉल तल, मास 238.38 वर्ग मी., श्री राम अपार्टमेंट-2, वार्ड सी-बीएचएल, लि., जीएच-3, सेक्टर-48, फरीदाबाद-121012 (हरियाणा) में श्री पवन कपूर के नाम में इम्कटेबल सॉल्टी मॉडरीजर आवासों सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।	23.7.2019	15.10.2019	रु. 3590396/-

तिथि: 17.10.2019, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक	
(ग्राम व पोस्ट-बिज्ञान, पानीत, हरियाणा-132103)	
दूरभाष: 0180-2688007/2688006 ई-मेल आईडी: iob3042@iob.in	
(कार्पोरेट IV) कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [निम्न 8 (1)]	
जबकि अधोस्तरीय ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की विनियम शक्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/धितवीकर्ताओं/अभ्यान्वितों हेतु सतर्क ट्रांसपॉसेट के (साझेदार श्री प्रयाग सिंह मलिक एवं श्रीमती सुमन मलिक), दुकान नं. 125, सेक्टर-25, ट्रांसपॉसेट नगर, पानीत-132103 (इसके पश्चात 'कर्जदार' कहा जायेगा), श्री प्रयाग मलिक पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीत, श्रीमती सुमन मलिक पत्नी श्री प्रयाग मलिक निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीत, श्री रजेश कुमार पुत्र अहले राम निवासी ग्राम चिपेट बिज्ञान जिला पानीत, श्रीमती राजबाला पत्नी श्री रजेश मलिक निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीत, श्रीमती नीना मलिक पत्नी श्री संदीप मलिक ग्राम रिसालू, जिला पानीत को वसूली की तिथि तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,82,10,056.52/- (रुपये एक करोड़ बीस लाख दस हजार छपप तथा बावन पैसे मात्र) तथा अनुवचन दर पर भावी ब्याज एवं करणों, प्रपत्रों आदि का कर्जित सूचना की प्रतिलिपि की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 10.05.2019 को एक मांग सूचना निवर्त की थी।	
(1) कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण पत्रधारक कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोस्तरीय ने कर्जित निम्नोक्त निगम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उस प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 16 अक्टूबर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कच्चा कर लिया है।	
विवेश रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संलग्नवार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संलग्नवार 30.09.2019 तक राशि रु. 1,88,52,114.52/- (रुपये एक करोड़ अठारसी लाख बावन हजार एक सौ चौदह तथा बावन पैसे मात्र) तथा मांग सूचना में उल्लिखित उपर्युक्त तिथि से मांग सूचना के निर्माण के पश्चात पुनर्भुगतान की राशि, यदि कोई हो, घटाकर उसके भुगतान की तिथि तक के सहमत अनुवचन दर पर ब्याज तथा बकायों, प्रपत्रों आदि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के भाग का विवरण होगा। कच्चा करने की तिथि तक 30.09.2019 तक बकाया देर रु. 1,88,52,114.52/- (रुपये एक करोड़ अठारसी लाख बावन हजार एक सौ चौदह तथा बावन पैसे मात्र) है जो भुगतान की तिथि तक अनुवचन दरों पर भावी ब्याज तथा बकायों, प्रपत्रों आदि सहित देय है।	
(2) प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हे उपलब्ध सम्प-सीमा के परिप्रेष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत आकृष्ट किया जाता है।	

श्री प्रयाग सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह एवं श्री सीतल कुमार् पुत्र श्री भल्ले राम के नाम पर दुकान नं. 125, सेक्टर-25, ट्रांसपॉसेट नगर, हुडा पानीत, हरियाणा, पिन 132103 पर स्थित सम्पत्ति का सफल भाग विक्रीकी सीमा निम्नलिखित है: पूर्व की ओर : सखीर की दुकान नं. 124, पश्चिम की ओर : खेड़ा साहब की दुकान नं. 126, उत्तर की ओर : सड़क, दक्षिण की ओर : गंग की दुकान। दिनांक : 16.10.2019, स्थान : पानीत अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-1, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली		बिक्री उद्घोषणा	
4था तल, जीवननारा भवन, पालियामेट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001			

आर.सी. नं. 122/2019 बिक्री उद्घोषणा सूचना तिथि: 25.9.2019 बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आचकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

यूबीआई बनाव वीना सिंघल एवं अन्य

सीडी नं. 1: वीना सिंघल, एच. नं. ई 20/48, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085

साथ ही: प्लॉट नं. बी-1676, एफ.एफ., खसरा नं. 497/168/2, ग्राम सधोरा कलॉन, शास्त्री नगर, नई दिल्ली-52

सीडी नं. 2: रजित सिंघल, एच. नं. ई 20/48, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085

साथ ही: प्लॉट नं. बी-1676, एफ.एफ., खसरा नं. 497/168/2, ग्राम सधोरा कलॉन, शास्त्री नगर, नई दिल्ली-52

जैसा कि पीपीसीएन अधिकांरी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए. नं. 99/2017/ डीआरटी-III, दिल्ली तिथि 4.2.2017 में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार प्रमाणपत्र के अनुसार आप के द्वारा देय रु. 13,86,187.36 (रुपए तेरह लाख छियासी हजार एक सौ सत्तारसी एवं पैंसे छत्तीस मात्र) तथा

तथा जैसा कि अधोस्तरीय ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की विक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि उसकी वसूली तत्क संयुक्त तथा पृथक् रूप से ओ.ए. दाखिल करने की तिथि 4.2.2017 से 12% साधारण ब्याज तथा अनुषंगिक खर्चों के साथ रु. 13,86,187.36 (रुपए तेरह लाख छियासी हजार एक सौ सत्तारसी एवं पैंसे छत्तीस मात्र) की राशि आप/सीडीज पर बकाया हो

गया है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थान आदेश की अनुपस्थिति में 21.11.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, सम्पत्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में) स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संघित की विक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से है। ई इंडिया प्रॉ.लि., गफफ प्रोटोलायम लिमिटेड नं. 301, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, प्रथम तल हरियाणा-122015, हेल्प लाइन नं. 91-124-4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, मो. 09813887931, ई-मेल आईडी: support@bankeaucations.com की वेबसाइट के माध्यम से की जायेगी।

यह विक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिनिधियों की संघित की होगी तथा उक्त संघित से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संघित को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में विक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूली को जाने वाली राशि संघित के भाग को बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में पूर्व बिक्री नही होगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोस्तरीय की पास जमा कर दिए होने का उन्को संतुष्टि के लिए प्रमाण पत्र कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्राप्यका या परोक्ष रूप से, वे बेचे जा रही संघित को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आचकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोस्तरीय की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामों के लिए अधोस्तरीय उत्तरदायी नहीं होगी।

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति को बिक्री नहीं की जायेगी का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	सम्पत्ति अर्थात् एच. नं. 1676, 1ला तल (विना छत के अधिकार के), शास्त्री नगर, दिल्ली	रु. 15,00,000/- ईएमडी: रु. 1,50,000/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लाया जाएगा।

3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोस्तरीय रवेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।

4. ईएमडी का भुगतान 19.11.2019 तक रिकवरी अधिकारी-1, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-III दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जाये







## भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने वादे पर कायम है और परमाणु ऊर्जा के हमारे संयंत्र पूरी तरह

सुरक्षित और बेहतर हैं।

उन्होंने कहा कि हम चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं और यह पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा उपयोग का मतलब बम बनाना नहीं है। 'इंडिया एनर्जी फोरम' के 11वें परमाणु ऊर्जा

सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा- भारत भाभा के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लक्ष्य पर कायम है। हम इसका सख्तियों का जीवन काल बढ़ाने और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक उपयोग कर रहे हैं। नए परमाणु ऊर्जा

संयंत्रों के बारे में सिंह ने कहा- हमारे ज्यादातर परमाणु संयंत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में हैं। हमने इसका विस्तार शुरू किया है। हम हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं। मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्य में यूरैनियम के स्रोत हैं जिसके उपयोग की जरूरत है।

**नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपकरण)  
ए-11, सेक्टर-24, नई दिल्ली - 201301  
फोन: 011-2412284 फैक्स: 2412397

**कॉस्टिक सोडा लाइ की खरीद**  
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पानीपत, बठिंडा और नंगल इकाईयों के लिए 1280 एमटी कॉस्टिक सोडा लाइ को खरीदने का आग्रह रखता है। निविदाकरण की विधि ई-निविदा है। निविदा की शर्तें और निबंधन, गाजटा मानचित्र और अन्य विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) या [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) देखें। इस ऑनलाइन ई-निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि 29.10.2019 को दोपहर 02.00 बजे तक है। तकनीकी मांगपत्रिका निविदा 29.10.2019 को दोपहर 02.30 बजे खोली जाएगी। शुद्धिपत्र (यदि कोई हो तो) केवल हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।  
कार्यकारी निदेशक (सामग्री)

**TRANSCORP INTERNATIONAL LTD.**  
Regd. Office Plot No. 3, BAF Pktda, Sec. 18A, Okhla, Phase-I, New Delhi-110075. CIN: U31500DL1994PLC235957  
Website: [www.transcorp.com](http://www.transcorp.com), Email: [procurement@transcorp.com](mailto:procurement@transcorp.com)  
Phone: 91-11-26119391-92, Fax: 91-11-26112936

**खरीद**  
सेमी (सूक्ष्म) कृषि मशीन और इन्जन (अपकाए) विनिर्माण, 2011 से अनुभव के लिए। यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय है कि कंपनी के इस्तेमाल के लिए आगामी वर्षा दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हुई तिथि है। इसका मतलब है कि अंतिम तक (एकल व संयोजित) के अनुबंधन पर अन्य कार्यों को करने से पहले मंचलवार विनांक 0.5.11.2019 को जल्द से जल्द अंतिम तिथि को जारी है। कॉस्टिक सोडा की वेबसाइट [www.transcorp.com](http://www.transcorp.com) के निवेशक द्वारा अनुभव पर भी उपलब्ध है।  
कृपे ट्रांसकोर्प इंटरनेशनल लि. के वेबसाइट [www.transcorp.com](http://www.transcorp.com) पर जाकर चेक की जा सकती है।  
दिनांक: 18.10.2019  
स्थान: नई दिल्ली

### कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा

ई-निविदा सूचना संख्या - RWD/SD/GODDA/09/2019-20

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाणु विपन्न का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	गोड्डा जिला के पोहोहाहाट प्रखंड के पहाड़पुर गाँव में पहाड़पुर टाला टोला और मंजीरी टोला के बीच जोरिया पर पुल निर्माण।	236.18400	4,72,500	10,000.00	15 माह

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 19.10.2019
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 28.10.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक
- ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा/मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रखंड एफओ एफओ पीओ भवन, धुर्वा, राँची में निविदा शुल्क, अग्रघन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय 30.10.2019 अपराह्न 05:00 बजे तक
- निविदा खोलने का स्थान - मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रखंड, एफओ एफओ पीओ भवन, धुर्वा, राँची
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 31.10.2019 अपराह्न 2:00 बजे
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा
- ई-निविदा प्रक्रिया का दूरभाष सं. - 9431943675 (संबन्धित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
- निविदा शुल्क राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा के पदनाम से देय हो देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट [www.jharkhandtenders.gov.in](http://www.jharkhandtenders.gov.in) एवं कार्यालय की सूचना पढ़ कर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा

PR 220191 Rural Development(19-20)D

### झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामोकाभामले) मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

ई-अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक : 17.10.2019  
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रामोकाभामले), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement प्रणालि से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	बाईडेंटी/फिकोशन संख्या/पंजीकृत संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)		कार्य समाप्ति की तिथि	टेंडर नं.
			अंश में	अग्र घन में		
1.	RDD/RWA/ GODDA/09/2019-20	गोड्डा से महाराज मुख्य सड़क मंजरी कलकत्ता स्थल मालखरिया उच्च विद्यालय, कम्प्यूटरों तक पथ का सुदृढीकरण कार्य (लंबाई 2.750 कि.मी.)	1,17,80,773.00	एक बारांडेड जख अरसी हजार रात की वितरल रूय मात्र	09 माह	द्वितीय

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 23.10.2019
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 01.11.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक।
- जिला नियंत्रण कक्ष, राँची में निविदा शुल्क, अग्रघन की राशि, शाप्य पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि - 04.11.2019 अपराह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 05.11.2019 अपराह्न 11:30 बजे तक।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता - मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामोकाभामले), झारखंड, राँची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, राँची।
- ई-निविदा प्रक्रिया का दूरभाष सं. - 0651-2207818
- निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामोकाभामले), कार्य प्रमंडल, गोड्डा के पक्ष में भुगतान होना जो लाटिया नहीं जायेगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट [jharkhandtenders.gov.in](http://jharkhandtenders.gov.in) में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी ई-प्रोक्युमेंट सेल

PR 220179 (Rural Work Department)19-20#D

### कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि. कानपुर नगर

पत्रांक: 26229/वैआ दिनांक : 17.10.19

अति अल्पकालीन निविदा सूचना  
1. महामहिम राज्यपाल, उ.प्र. की ओर से उ.प्र. लोक निर्माण विभाग के 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के पंजीकृत निविदादाताओं से नीचे दर्शाई गयी निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जनपद	कार्य का विवरण	लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षों काल सहित)
1	कानपुर नगर	गुरुदेव चौराहे से चिड़ियाघर होते हुए कम्पनीबाग चौराहे तक कटिंग भाग में मरम्मत का कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन
2	कानपुर नगर	चिड़ियाघर चौराहे से कर्बला मार्ग के कटिंग भाग में रेस्टोरेशन का कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन
3	कानपुर नगर	कम्पनीबाग से कोहना थाना होते हुए परमिया नाला मार्ग के कटिंग भाग में रेस्टोरेशन कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन
4	कानपुर नगर	एन.एच.-91 लहहन से सर्वोत्तम मार्ग में कटिंग भाग के रेस्टोरेशन का कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन

- कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) उपरोक्त तालिका कालम सं. 7 में दर्शाया गया है।
- निविदा प्रपत्र करने के उपरान्त निविदा 90 दिन तक वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात नहीं ली जा सकेगी।
- निविदा प्राप्त संबंधित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक दिनांक 30.10.2019 से 04.11.2019 तक रु. 944.00 (स्टेशनरी चार्जज रु. 800+144 जी.एस.टी.) डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। ड्राफ्ट (शिखर बैंक से निर्गत) द्वारा भुगतान "अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., कानपुर नगर" के पक्ष में उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में किया जायेगा। दिनांक 05.11.2019 अपराह्न 4.00 बजे तक प्राप्ति। का अतिरिक्त भुगतान किये जाने पर निविदा पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट से भेजी जा सकती है। डाक द्वारा विलम्ब के लिये निविदा आमंत्रण प्राधिकारी जिम्मेदार न होंगे।
- निविदा प्रपत्र एवं अधिशासी/ अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र में भिन्नता की दशा में कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही वैध माना जायेगा।
- निविदा उपरोक्त अतिरिक्त कार्यालयों में दिनांक 05.11.2019 को सायं 03.00 बजे तक प्राप्त कराया जा सकती है। निविदा की दरें बिड दिनांक 06.11.2019 को सायं 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) कार्यालय, कानपुर नगर में इच्छुक ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। कार्यालय अवकाश की दशा में निविदा अगली तिथि को उक्तवचन प्राप्त कर खोली जायेगी।
- निविदा से संबंधित जानकारीयें हेतु 01.11.2019 को 4.00 बजे सायं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय (कालम-7) में निविदा की पूर्व बैठक की जायेगी, जिसमें "निविदा दाता को निर्देश" के कलाज 9.2 में वर्णित जानकारीयें स्पष्ट की जायेगी।
- निविदा के साथ, जैसा कि बिड प्रपत्र में अंकित है, निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की वैधता को बिड सिक्वियरिटी संलग्न की जायेगी।
- निविदादाता को अपने ब्लड रिलेजनाशिय अथवा उनके निकट रिश्तेदार जो प्रभागीय लेखाधिकारी अथवा निविदा आमंत्रण अधिकारी के स्तर तक, के कार्यक्षेत्र में निविदा प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- राजपत्रित अथवा अराजपत्रित अभियन्ता जो राज्य/ केंद्रीय सेवा में हो, सेवानिवृत्ति के उपरान्त दो वर्ष तक निविदा हेतु बिना शासकीय अनुमति के पात्र नहीं होगा। यदि बाद में इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आता है तो निविदादाता को निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा से संबंधित क्वालिफिकेशन सूचना तथा निविदा के अर्हता, प्लान, विशिष्टियां, मानचित्र, मात्रा का विवरण एवं निविदा के शर्तों की जानकारी अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, से दिनांक 30.10.2019 से 05.11.2019 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
- आपराधिक पृष्ठभूमि के निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- राज्य अधिवचना संघ में पंजीकृत व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- शासनदेश संख्या 622/ 23-02-2012-2 आडिट/ 08 टी.सी.-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10% Below टेण्डर पर अतिरिक्त सिक्वियरिटी परफोमेंस गारंटी ली जाएगी।
- शासनदेश संख्या 346/0 23-07-08- 41 एन.एस.ए./ 54 टी.सी. दिनांक 28.07.2009 में निहित निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ठेकेदारों को बिड के साथ आगोपित धराशिका को 2 प्रतिशत तालिका के कॉलम 4 के अनुसार बिड सिक्वियरिटी देनी होगी तथा अवशेष बिड सिक्वियरिटी स्वीकृति प्रपत्र जारी होने पर अनुबंध गठन करने के समय देनी होगी।
- डिफेंस लायबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- निविदा शुल्क नगद अथवा रु 800.00 व रु. 144.00 के अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

हस्ता./-  
(एस. पी. ओझा)  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि.,  
कानपुर नगर

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2019

स्थान: नई दिल्ली

रिक्त/अनुपस्थित प्रोफेशनल: अर्होत्पन्न सेल प्रार्थित लिमिटेड

पंजीकृत संख्या: IBB/MVA-003/IP-N00073/2017-18/10583

**MMTC LIMITED**  
Teaching facilities, adding scope

कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीच्युशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
Phone #011-24381249 (Direct), Pbx - 011-24362200  
CIN NO.:LS1909L196301016003

निविदा सूचना सं. MMTC/CO/Projects/Abhraknagar/Vol.III तिथि: 10.10.2019  
एमएमटीसी द्वारा एमएमटीसी के अग्रक रण प्लानट में निम्न कार्यो के मूल्यांकन के लिये गणनाकार्य की भर्ती के लिये बोलीयां आमंत्रित है।  
(i) पलाउट एवं मशीनरी (बिक्री पर अनुमानित उगाही-योग्य मूल्य) का मूल्यांकन तथा दी जाने वाली मारिक प्रत्याशित किराया दर्शाए।  
(ii) भूमि का मूल्यांकन (अनुमानित मासिक किराया जो उप पट्टा पर प्रस्तावित हो सकता है)  
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर-1, 3रा तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीच्युशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में पूर्ण की गई बोली जमा करने की अंतिम तिथि 11.11.2019 के 3.00 बजे अप. तक है। निविदा का सम्पूर्ण विवरण एमएमटीसी की वेबसाइट [www.mmtclimited.com](http://www.mmtclimited.com) तथा <http://eprocure.gov.in> पर उपलब्ध है।  
शुद्धिपत्र/संबन्धन यदि कोई जारी की जाती है, केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रकाशित होगी।  
अतिरिक्त महा प्रबंधक (परियोजना एवं जीटी)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाणु विपन्न का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	गिरिडीह जिला के गावां प्रखण्ड अंतर्गत आर०ई०ओ० रोड माला निमाडीह से आरागारो महादेव मंदिर के सामने (सकरी नदी में) पुल निर्माण (लम्बाई-309.80 मी०)	987.32800	1974700.00	10000.00	24 माह
2.	वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि				21.10.2019
3.	ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय				30.10.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक
4.	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह/मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रखंड, एफओ एफओ पीओ भवन, धुर्वा, राँची में निविदा शुल्क, अग्रघन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय				31.10.2019 अपराह्न 05:00 बजे तक
5.	निविदा खोलने का स्थान				मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रखंड, एफओ एफओ पीओ भवन, धुर्वा, राँची
6.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय				30.10.2019 अपराह्न 2:00 बजे
7.	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता				कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह
8.	ई-निविदा प्रक्रिया का दूरभाष सं. -				09431323435
9.	निविदा शुल्क राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह के पदनाम से देय हो देना होगा।				विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट <a href="http://www.jharkhandtenders.gov.in">www.jharkhandtenders.gov.in</a> एवं कार्यालय की सूचना पढ़ कर देखा जा सकता है।

PR.202267 Rural Development(19-20):D

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह

**महानगर मुद्रण टेलीफोन निगम लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपकरण)  
सुशांर लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

**निविदा आमंत्रण सूचना**  
एम्टीएनएल नई दिल्ली की ओर से निम्नांकित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।  
1. सी एजीएम (आईटी-टीपी) बिल प्रिंट/2019-20 एम्टीएनएल दिल्ली के पीएसटीएल और एपीएसएम एलओके के बिना की प्रिंटिंग के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित हैं (अनुमानित लागत रु. 78,00,149/-) - साधारण।  
2. सी एजीएम (एपीएमटी)/5 फेडर मीडिया/केएफ केबल/2018-19/01 5 फेडर मीडिया/केएफ केबल (ए/ए) की आपूर्ति के लिए दो मार्ग (भाग-क तकनीकी मांगपत्रिका और भाग-ख वित्तीय बोली) में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित हैं (अनुमानित लागत रु. 19,58,000/-)।  
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <http://www.eprocure.gov.in>, <http://eprocure.gov.in/eprocure/app>, [www.mtnldehi.in](http://www.mtnldehi.in) और <http://www.tenders.gov.in> पर लागू आन करें।

**भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड**  
(भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)  
नोट मुद्रण नगर, मैसूरु - 570 003

**राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (खुली निविदा)**  
1. एक्सप्रेस निविदा - निविदा संख्या 080/MYS/MMD/2019-20 - अनुमानित मूल्य: रु 38.52 लाख - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 04.11.2019 है।  
2. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में पर्सोनेल कंस्ट्रुटर्स की आपूर्ति और स्थापना - निविदा संख्या 081/MYS/MMD/2019-20 - अनुमानित मूल्य: रु 40.65 लाख - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.11.2019 है।  
3. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में कर्मचारियों के लिए बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति, - निविदा संख्या 082/MYS/MMD/2019-20 - अनुमानित मूल्य: रु 34.36 लाख - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.11.2019 है।  
4. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में सीएसआर के तहत मेडिकल इक्विपमेंट्स की आपूर्ति, स्थापना और कालिभर्ती - निविदा संख्या 083/MYS/MMD/2019-20 - अनुमानित मूल्य: रु 93.87 लाख - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.11.2019 है।  
5. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में शुटिलरी एवोल्यूशन/मैट्रेस और मुख्य प्रेशर बन का (बाहरी) रि-पेट्रीटी - निविदा संख्या 084/MYS/CVIL/2019-20 - अनुमानित मूल्य: रु 96.00 लाख। उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.11.2019 है।  
निविदा दाताएं और अन्य विवरण डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट [www.brnmpl.co.in](http://www.brnmpl.co.in) पर जाएं। आगे जो भी विवरण या संशोधन होगा उसे सिर्फ हमारी वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

**एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड**  
(पूर्व में एयू फाईनेन्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना) (CIN:L36911RJ1996PLC011381)  
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, कृष्णनगर, अजमेर रोड, नयापूर, बंगलूरु-560001

**पारिशिष्ट 10 (द्वितीय नियम 9 (1) कक्षा सूचना)**  
अधिक, अधोहस्ताक्षरताएं एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेन्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना) का प्राथमिक अधिकारी होने हुए "वित्तीय आरक्षण" का प्रतिपत्तिकरण एवं पूर्वान्ह और प्रतिपत्तिकरण प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 का 54)] "और प्रतिपत्तिकरण (प्रवर्तन) नियमों के नियम (3) के तहत प्रदान अधिकारों के अनुबंधों में मांग सूचना 16/05/2019 कागज खाली संख्या: L9001060115300635 निर्गमित की जिसमें मांग करने हुए सूचना अधिन कृष्णन लिमिटेड (अपूर्ति/ बन्धककर्ता), हसीर कृष्णन (सह-अपूर्ति/ बन्धककर्ता), श्रीमती स्नेह देवी (सह-अपूर्ति) से निर्गत एवं निर्गमित संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि एवं नोटिस कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरताएं ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा संपर्कित प्रतिपत्तिकरण प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदान अधिकारों के अनुबंधों में प्रतिपत्तिकरण प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता को विशिष्टियन्ता और सर्वसाधारण को सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरताएं ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा संपर्कित प्रतिपत्तिकरण प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदान अधिकारों के अनुबंधों में प्रतिपत्तिकरण प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन का एतद द्वारा संपर्कित साध व्यवहार संख्या 7377335/- (अक्षर तहत लाख लिखत हजार तीन सौ पचास मात्र) की राशि दिनांक 16/05/2019 तक तथा आगे का व्यवहार प्रवर्तन नियमों के तहत प्रदान अधिकारों के लिये 15 माह अक्टूबर वर्ष 2019 को अधिनियम का विवरण।  
अपूर्ति/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर अपूर्ति/बन्ध







## खबर कोना



एफआइएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए चुनी गई पुरुष और महिला टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल।

### मेरी कॉम की अकादमी में गुडईयर के सहयोग से नया रिंग

इंफ्ल, 18 अक्टूबर (भाषा)।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कॉम की यहां स्थित मुक्केबाजी अकादमी में टायर निर्माता कंपनी गुडईयर इंडिया की मदद से नया रिंग और कुछ अन्य आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। इस रिंग का औपचारिक उद्घाटन मेरी कॉम और उनके पति ओनलर कोम ने किया जो कि अकादमी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा कंपनी ने अकादमी में भोजन कक्ष और रसोईघर के पहले चरण के निर्माण में भी मदद की। छठीस वर्षीय मेरी कॉम ने हाल में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था जो उनका इस प्रतियोगिता में रेकार्ड आठवां पदक है। मेरी कॉम राज्यसभा सांसद भी हैं।

### लेग स्पिनर नहीं उतारने पर बांग्लादेश के दो कोच बर्खास्त

ढाका, 18 अक्टूबर (एएफपी)।

अदद लेग स्पिनरों की खोज में लगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय क्रिकेट लीग (एनसीएल) में लेग स्पिन गेंदबाजों को अंतिम एकादश में शामिल नहीं करने पर प्रथम श्रेणी स्तर के दो कोच को बर्खास्त कर दिया। बांग्लादेश को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए अदद लेग स्पिनर की तलाश है। यही नहीं बल्लेबाजों को घरेलू मैचों में लेग स्पिन खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता और यही वजह है कि हाल में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने शुक्रवार को पुष्टि की कि निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण दो कोच को बर्खास्त कर दिया गया है। ढाका की टीम में लेग स्पिनर जुबैर हुसैन और खुलना की टीम में रिशाद हुसैन को हाल में खेले गए प्रथम श्रेणी मैचों के लिए अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया था।

### टी-10 में टीम अबुधाबी के कोच होंगे ट्रेनर बेलिस

अबुधाबी, 18 अक्टूबर (भाषा)।

विश्व कप विजेता कोच ट्रेनर बेलिस 15 नवंबर से शुरू होने वाले टी-10 टूर्नामेंट में टीम अबुधाबी के कोच होंगे जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली उसकी अगुआई करेंगे। खिलाड़ियों के वार्षिक ड्राफ्ट के अनुसार आठ टीमों में 110 खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें श्रीलंका के लेसिथ मलिंगा, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कोरेन पोलाड और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर शामिल हैं। टीम अबुधाबी टूर्नामेंट की आठवीं टीम है जिसके आइकन खिलाड़ी मोईन अली हैं। इसके अलावा श्रीलंका के निरोशन डिकवेल्ला, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन और आमिर भी टीम का हिस्सा हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी मौजूदा चैंपियन नॉर्दन वॉरियर्स के आइकन खिलाड़ी होंगे।

# अंतिम टैस्ट में भी जोरदार भिड़ंत की उम्मीद

टैस्ट चैंपियनशिप के कारण दांव पर लगे हैं अहम 40 अंक

मेरे पंत के बीच अच्छी समझ : साहा

### मैच का समय

सुबह 9:30 से

रांची, 18 अक्टूबर (भाषा)।

भारतीय टीम शनिवार से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टैस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। भारत पहले ही श्रृंखला जीत चुका है जिससे यह मैच औपचारिक लग रहा है। लेकिन विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जा रही टैस्ट श्रृंखला के कारण अहम 40 अंक दांव पर लगे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम भी इस अंक के लिए अंतिम मैच में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी। भारत ने पहले दो टैस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका पर हर विभागा में अपना दबदबा बनाया। उसने विशाखापत्तनम में 203 रन से जीत दर्ज की और फिर पुणे टैस्ट को पारी और 137 रन से जीतकर फ्रीडम ट्रॉफी फिर से हासिल की। विश्व चैंपियनशिप में भारत के अभी चार मैचों में 200 अंक हैं और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर 140 अंकों की बड़ी बढ़त बना रखी है। कोहली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अंतिम टैस्ट मैच में भी काफी कुछ दांव पर लगा है और टैस्ट किसी भी तरह से हिलायी नहीं बरतेगी।

**भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी महजूत**  
अंतिम टैस्ट मैच से पूर्व भारतीय टीम में बल्लेबाजी या गेंदबाजी में कोई खास कमजोरी नजर नहीं आती है। भारतीय शीर्ष क्रम ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा ने लंबे प्रारूप में सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने पहले टैस्ट मैच में पहली बार पारी का आगाज करते हुए दोनो पारियों में शतक लगाए। मुंबई के इस



तीसरे टैस्ट की पूर्व संस्था पर अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय स्पिनर आर अश्विन और मुख्य कोच रवि शास्त्री।

बल्लेबाज के साथी मयंक अग्रवाल ने विशाखापत्तनम में दोहरा शतक लगाया तो पुणे में भी वह सैकड़ा जमाने में सफल रहे। पुणे में हालांकि कोहली ने 254 रन की जादुई पारी खेली जो उनके करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। रोहित पुणे में नहीं चल पाए थे और वह इसकी भरपाई यहां करना चाहेंगे।

**कुलदीप बाहर, स्थानीय स्पिनर नदीम टीम में**  
बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला जिन्हें चाइनामैन कुलदीप यादव के कंधे की चोट के कारण बाहर होने से भारतीय टैस्ट टीम में शामिल किया गया। नदीम झारखंड और भारत ए के लिए कई बार शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। झारखंड के लिए लगातार सत्र में 50 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं। 30 साल के इस

स्पिनर ने 110 प्रथम श्रेणी मैचों में 424 विकेट चटकाए हैं जिसमें 19 बार वह पांच विकेट जबकि पांच बार 10 विकेट हासिल कर चुके हैं।

**स्पिनरों के अनुकूल रांची की पौच**  
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसिस पहले ही कह चुके हैं कि रांची की पिच स्पिनरों के अनुकूल होगी और ऐसे में कुलदीप यादव के रूप में तीसरा स्पिनर भी भारतीय एकादश में जगह बना सकता है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने विशाखापत्तनम में कुछ दम दिखाया था लेकिन पुणे में वे नाकाम रहे थे। केवल पुछल्ले बल्लेबाजों ने ही भारतीय गेंदबाजों को कुछ परेशान किया। डुप्लेसिस ने ऐसे में अनुभवी बल्लेबाजों से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए कहा है।

निकहत की मांग पर रिजीजू ने कहा

## देश के हित में फैसला करने के लिए कहूंगा

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

खेल मंत्री किरन रिजीजू ने मुक्केबाज निकहत जरीन और एमसी मेरी कॉम के बीच चल रहे मामले में स्पष्ट किया कि वह केवल महासंघ को देश और खिलाड़ियों के हित में सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने के लिए ही कह सकते हैं। निकहत ने गुरुवार को रिजीजू को पत्र लिखकर चीन में अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए टीम चयन से पहले मेरी कॉम के खिलाफ ट्रायल मुकाबला आयोजित करने की मांग की थी।

इससे पहले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) ने कहा था कि मेरी कॉम के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वह उन्हें चुनने का इरादा रखता है। इसके बाद ही जरीन ने यह पत्र लिखा। रिजीजू ने जरीन के पत्र के जवाब में कहा कि मैं निश्चित तौर पर मुक्केबाजी महासंघ को देश, खेल और खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करने के लिए कहूंगा।

मंत्री को हालांकि खेल संघों द्वारा खिलाड़ियों के चयन में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि खेल संघ ओलंपिक चार्टर के अनुसार स्वायत्त हैं। मेरी कॉम ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह बीएफआइ के फैसले के अनुसार चलेगी। बीएफआइ ने पहले कहा था कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक विजेता मुक्केबाजों का ही ओलंपिक क्वालीफायर के लिए सीधे चयन होगा।

हासिल किए। पुरुषों में विश्वनाथ सुरेश (46 किग्रा) और विश्वामित्र चोंगथम (48 किग्रा) ने स्वर्ण जीते। राष्ट्रीय चैंपियन कल्पना (46 किग्रा), प्रीती बहिया (60 किग्रा), तशवीर कोर संधू (80 किग्रा) और अल्लिया तरन्नुम पटान

## एशियाई चैंपियनशिप में मुक्केबाजों ने जीते 21 पदक

जनसत्ता संवाददाता/भाषा नई दिल्ली, 18 अक्टूबर।

भारतीय मुक्केबाजों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह में आयोजित एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने छह स्वर्ण, नौ रजत के साथ कुल 21 पदक हासिल किए। टूर्नामेंट में 26 देशों ने भाग लिया था जिनमें भारत कुल पदकों के मामले में शीर्ष पर रहा। हालांकि भारत तालिका में उज्बेकिस्तान (20 पदक) के बाद दूसरे स्थान पर रहा जिसने आठ स्वर्ण जीते। भारतीय पुरुष टीम ने दो स्वर्ण, तीन रजत और इतने ही कांस्य पदक जीते जबकि महिला टीम ने गुरुवार शाम समाप्त हुए टूर्नामेंट में चार स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदक

जिते (80 किग्रा से अधिक) ने महिलाओं के वर्ग में स्वर्ण जीते। योगेश कागड़ा (63 किग्रा), जयदीप रावत (66 किग्रा) और राहुल (70 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में जबकि तमन्ना (48 किग्रा), तनू (52 किग्रा), नेहा (54 किग्रा), खुशी (63 किग्रा), शारवरी कल्यांकर (70 किग्रा) और खुशी (75 किग्रा) ने महिलाओं के वर्ग में रजत पदक अपने नाम किए।

महिलाओं के वर्ग में रिंकू (50 किग्रा), अंवेश्वरी देवी (57 किग्रा) और माही लामा (66 किग्रा) जबकि विजय सिंह (50 किग्रा), विक्टर सिंह शेखोम (52 किग्रा) और वंशज (60 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। टूर्नामेंट में 26 देशों के 293 (170 पुरुष और 69 महिला) मुक्केबाजों ने भाग लिया था।

महिला टीम के लिए सहयोगी स्टाफ के चयन पर विवाद

बीसीसीआइ

इडुल्जी और रंगास्वामी ने नियुक्ति पर उठाए सवाल

## पुरुष टीम के साथ भी क्या आप ऐसा ही करेंगे?

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा)।

सीओए सदस्य डायना इडुल्जी और बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद की नई सदस्य शांता रंगास्वामी ने महिला राष्ट्रीय टीम के लिए सहयोगी स्टाफ की 'असंवैधानिक' नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी को पत्र लिखकर अपनी बात रखी है। जीएम (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम महिला क्रिकेट का कार्यभार संभालते हैं। इन नियुक्तियों के लिए वह संदेह के घेरे में हैं।

हेमलता काला की अगुआई वाले महिला चयन पैनल ने एक दिन पहले सीईओ को लिखकर दावा किया कि उन्हें सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रखा गया था। इसके एक दिन बाद पूर्व भारतीय कप्तान इडुल्जी और रंगास्वामी ने राष्ट्रीय महिला टीम के साथ इस तरह के रवैये की आलोचना की। बीसीसीआइ संविधान के अनुसार



शांता रंगास्वामी

चयनकर्ता ही पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीम के सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। हाल में पुरुष टीम के सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। इडुल्जी ने पत्र में लिखा, 'मैं महिला चयनकर्ताओं द्वारा आपको लिखे गए ईमेल में लिखी बातें पढ़कर हैरान हूँ कि वीडियो विश्लेषक के चयन के लिए गलत प्रक्रिया का

पालन किया गया।' उन्होंने लिखा, 'यह और भी चिंता की बात है कि पुष्कर सावंत वेस्ट इंडीज के लिए फ्लाइट भी बुक करा चुके हैं जिन्हें सबा करीम और एनसीए इस पद पर चाहते थे। यह पूरी प्रक्रिया ही आंखों में धूल डोकेने वाली लगती है। चयनकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें महिला टीम के गेंदबाजी

पैनल के साथ भी ऐसा ही करोगे?' और क्षेत्ररक्षण कोच की नियुक्ति के लिए भी विश्वास में नहीं लिया गया था। उन्हें सिर्फ वीडियो विश्लेषक की भूमिका के लिए साक्षात्कार कराने के लिए कहा गया जिसके लिए प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हुई। इडुल्जी और रंगास्वामी ने दावा किया कि वीडियो विश्लेषक की भूमिका के लिए भी नियमों का उल्लंघन किया गया।

इडुल्जी ने कहा कि मुझे शांता रंगास्वामी से भी ईमेल मिला है जिन्हें बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद का सदस्य नामित किया गया है। इसे आपको और चयनकर्ताओं को भी भेजा गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये चीजें जानबूझकर की गई हैं ताकि शीर्ष पर बैठे लोग अपने व्यक्तियों को गलत तरीके से इन पदों पर बिठा लें। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने लिखा, 'यह राष्ट्रीय भारतीय टीम है जो यात्रा कर रही है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मुझे हैरानी है कि क्या आप पुरुष टीम के साथ भी ऐसा ही करोगे?'

## फाइनल से पहले भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन से ड्रां खेली

जोहोर बाहरू (मलेशिया), 18 अक्टूबर (भाषा)।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम और ब्रिटेन ने शुक्रवार को यहां नौवें सुल्तान जोहोर कप के अंतिम राउंड रोबिन मैच में 3-3 से ड्रां खेली। पहले क्वार्टर में भारत ने कब्जा बनाए रखा और ज्यादातर हमलों में आगे रहे लेकिन ब्रिटेन के डिफेंस में संघ नहीं लग सका। दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने कोशिश जारी रखी जिसमें गुरसाहिबजीत सिंह का शॉट नाकाम रहा। ब्रिटेन ने इस अंतर में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला मौका मिला और इयोन वाल की ड्रैगफ्लिक से टीम ने पहला गोल कर दिया। ब्रिटेन ने फिर 23वें

मिनट में एंड्रयू मैककोनेल के गोल से बढ़त दोगुनी कर दी और ब्रेक तक स्कोर 2-0 रहा। शिलानंद लकड़ा ने इस अंतर को कम किया और फिर मंदीप मोर ने 51वें मिनट में स्कोर 2-2 से बराबर किया।

ब्रिटेन को पता था कि उन्हें फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए महज ड्रां की जरूरत है। सर्वकल के पास दिलीप्रीत को गिराए जाने के बाद भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर शारदानंद तिवारी ने भारत को बढ़त दिला दी। हालांकि मैथ्यू रेशॉर्न ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर 3-3 से बराबर कर सुनिश्चित किया कि दोनों टीमों शनिवार को एक दूसरे से फाइनल खेलें।

### हॉकी

## सरफराज टैस्ट और टी-20 कप्तान पद से बर्खास्त

कराची, 18 अक्टूबर (भाषा)।

श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला गंवाने के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को सरफराज अहमद को टैस्ट और टी-20 कप्तान पद से बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आधिकारिक बयान में कहा कि अनुभवी बल्लेबाज अजहर अली आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टैस्ट मैचों में टैस्ट टीम की अगुआई करेंगे जबकि बाबर आजम नवंबर में होने वाले इस दौर में टी-20 टीम का जिम्मा संभालेंगे। सरफराज पिछले दो वर्षों से तीनों प्रारूपों में कप्तान थे। उनकी अगुआई में पाकिस्तान ने 2017 में आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। टैस्ट और वनडे में उनकी अगुआई में पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे गिरी जबकि श्रीलंका के खिलाफ हाल में टी-20 श्रृंखला में उसने सभी मैच गंवाए।